



पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है:मोदी

चंडीगढ़। पंजाब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जालंधर में 5,470 करोड़ रुपये की रेलवे और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं जिनमें जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इसके साथ ही पंजाब , हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में असली बदलाव भाजपा

ही ला सकती है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री के भाषण कि 5 बड़ी बातें।

***पीएम मोदी ने रैली में कहा,** पंजाब को विकसित, आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब में नया निवेश आए, पंजाब में रोजगार के नए अवसर बनें, पंजाब में बने प्रोडक्ट दुनिया के कोने-कोने में पहुंचे, ये काम भाजपा ही करेगी।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं होता। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा, इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी

है, वो किसके पास रहेगी।

‘कुछ लोग पार्थ पवार का राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश कर रहे’, सुनेत्रा पवार को लिखे पत्र में हृष्टक की फूट का खुलासा महादेव ऐप केस में गिरफ्तारी के बाद ऋष्टक का बड़ा एक्शन, विकास गर्ग पार्टी से निष्कासित

पंजाब में कानून-व्यवस्था बेहाल

प्रधानमंत्री बोले, पंजाब में आज क्या हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून-व्यवस्था



बेहाल है। कब कहां गैंगवॉर हो जाए, किस दिशा से गोतियां चलने लगे, कोई कह नहीं सकता। यहां व्यापार-कारोबार करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आगे कहा, पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं है, आए दिन थानों पर

अटैक होते हैं। सबसे दुखद तो ये है कि पंजाब का भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है। नशे के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं, पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है।

खेल में आगे बढ़ने के लिए किया प्रोत्साहित

जालंधर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने देखा है कि पंजाब के युवा खेल के मैदान में भारत का गौरव और सम्मान कैसे बनाए रखते हैं। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर

है। ‘खेलो इंडिया अभियान’ और ‘खेलो इंडिया खेल नीति’ विशेष रूप से आपके लिए शुरू की गई है। भारत में एक नई खेल अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है और इस अर्थव्यवस्था के केंद्र में जालंधर का खेल निर्माण तंत्र है। उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया और उनके साथ कई समझौते किए गए हैं। मैं सभी युवाओं से खेलों में भाग लेने और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने का आग्रह करता हूं। हमारी सरकार हर संभव तरीके से आपके साथ खड़ी है।

विकास के प्रति प्रतिबद्ध

पंजाब में सभी विकास कार्य ठप्प हो गए हैं। भारत सरकार की योजनाओं को मात्र करके अपने नाम से प्रचारित किया जा रहा है और उन्हें अपनी योजना के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है लेकिन पंजाब के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राज्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में तीखी बहस

डॉ. महंत ने सरकार पर लगाए 136 आरोप,- अजय चंद्राकर ने किया पलटवार

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लंबी और तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकार के खिलाफ 136 बिंदुओं का आरोप पत्र पेश करते हुए कहा कि यह केवल विपक्ष का नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की आवाज है। उन्होंने किसानों, महिलाओं, युवाओं, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी अधिकार, हसदेव अरण्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा।

डॉ. महंत ने कहा कि सरकार के कार्यकाल के हर सप्ताह जनता के साथ एक नया धोखा और नाकामी जुड़ी है। उन्होंने हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई, आदिवासी क्षेत्रों में खनन, अपराध की बढ़ती घटनाएं, महिलाओं के खिलाफ अपराध, धान खरीदी, मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, महतारी वंदन योजना, माइक्रो फाइनेंस, चिटफंड, शराब बिक्री और पर्यावरण जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों, आदिवासियों और गरीबों के हितों की अनदेखी की जा रही है। अपने भाषण के दौरान डॉ. महंत ने संत पवन दीवान की कविता का उल्लेख किया, जिस पर मंत्री ओपी चौधरी और भाजपा



विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताई। महंत ने स्पष्ट किया कि यह उनके निजी विचार नहीं, बल्कि संत पवन दीवान की रचना है।

महंत ने कहा कि सरकार आलोचना सहन नहीं कर पा रही है और प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगड़ चुकी है। उन्होंने विभिन्न जिलों में हुई हत्या, दुष्कर्म और अन्य आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार को जंगलराज का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पर किसानों और आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब देते हुए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका केवल औपचारिकता निभाने तक सीमित रह गई है और कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ ठोस मुद्दे नहीं हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पीएससी भर्ती घोटाला,

भारतमाला परियोजना, शराब घोटाला, गोबर खरीदी, गोधन न्याय योजना, विद्युत शुल्क मामी, राजीव मितान क्लब, उद्योगों को लाभ पहुंचाने और विभिन्न योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं जैसे कई विवाद सामने आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने विकास के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि विष्णुदेव साय सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, धर्मांतरण विरोधी कानून, कौशल विकास, रेलवे अधोसंरचना, मॉडकल कालिंजों के विस्तार और अन्य विकास कार्यों को गति दी है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता और सुशासन के साथ काम कर रही है। बहस के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अजय चंद्राकर के बीच भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला, जिससे सदन का माहौल कई बार गर्म हो गया। दिनभर चली चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने तर्कों के साथ सरकार के कामकाज और पिछली सरकार के कार्यकाल को लेकर एक-दूसरे पर जमकर राजनीतिक हमले किए। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई इस बहस ने विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया।



नई दिल्ली। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर किसी रेल दुर्घटना में मृत यात्री के शव से ट्रेन का टिकट बरामद नहीं होता है तो केवल इसी आधार पर उसके परिजनों को मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने रेलवे क्लेमस ट्रिब्यूनल (ऋष्ट्र) और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द करते हुए साल 2015 में चलती ट्रेन से गिरकर जान गंवाने वाले एक व्यक्ति की पत्नी को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

जस्टिस संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शब्दों की विधवा की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि आरसीटी

टिकट न होने पर भी रेल दुर्घटना में मिलेगा मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट

और हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मुआवजे का दावा खारिज कर दिया था कि दुर्घटना के बाद मृतक का टिकट नहीं मिला इसलिए यह साबित नहीं हो सका कि वह एक वास्तविक (बोना फाइड) यात्री था।

‘अपने फैसले में पहले के न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा, कल्याणकारी कानूनों की व्याख्या उनके उद्देश्य और विधायिका की मंशा को आगे बढ़ाने के लिए उदार और उद्देश्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए। उनकी शाब्दिक या अत्यधिक संकीर्ण व्याख्या नहीं अपनाई जानी चाहिए। मूल उद्देश्य यह है कि कानून के पीछे की मंशा प्रभावी रूप से लागू हो सके। सुप्रीम

कोर्ट ने कहा कि तकनीकी आधारों या प्रक्रियागत कर्मियों के कारण कानून के कल्याणकारी उद्देश्य को विफल नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य के एक अंग होने के नाते रेलवे के लिए इतना संकीर्ण और सीमित दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं है। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि रेलवे अधिनियम की धारा 124 के तहत मुआवजे की कार्यवाही ‘नो-फॉल्ट लाइबिलिटी’ (हथ-सबुद्धबद्ध ऋद्धुद्धबद्धह4) के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उद्देश्य रेलवे की अप्रिय घटनाओं के पीड़ितों या उनके परिजनों को बिना किसी लापरवाही का प्रमाण दिए त्वरित मुआवजा उपलब्ध कराना है।



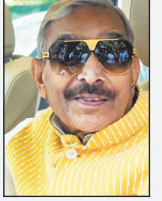
शामली अब आतंक का नहीं विकास का प्रतीक : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शामली जिले में आए बड़े बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह जिला कभी अराजकता और डर का केंद्र था, लेकिन अब यहाँ विकास और कनेक्टिविटी का माहौल है। शामली में बोलते हुए उन्होंने याद दिलाया कि एक दशक पहले यह जिला आतंक और डर का प्रतीक था, जहाँ बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन और गुंडागर्दी होती थी, बुनियादी ढाँचे का विकास रुका हुआ था और सुरक्षा का भी अभाव था। उन्होंने कहा कि दस साल पहले शामली चर्चा का विषय थी, लोग सोचते थे कि शामली जिला कहाँ है, क्योंकि यह डर और दहशत का प्रतीक बन गया था। बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा था, खुलेआम गुंडागर्दी होती थी और कोई भी सुरक्षित नहीं था। विकास के काम रुक गए थे, युवा निराश थे, किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, महिलाएँ और लड़कियाँ बाहर निकलने से डरती थीं, उद्योग ठप हो गए थे और सड़कें गड्ढों से भरी हुई थीं।



महिला आरक्षण की आड़ में आ रहा परिसीमन बिल : कांग्रेस

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि महिला आरक्षण बिल पर उनकी पार्टी का रुख साफ़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल लाया जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस परिसीमन बिल का विरोध करेगी और बताया कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। तिवारी ने मीडिया से कहा कि हमने उनसे परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा है। पहले भी ऐसा ही पत्र भेजा गया था और अब फिर से भेजा गया है। महिला आरक्षण पर हमारा रुख साफ़ है। अगर महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लाया जाता है, तो हम उसका विरोध करेंगे। गुरुवार को खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के संबंध में सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया।



राजद ने भाजपा प्रत्याशी के डिग्री पर उठाया सवाल

पटना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा के चुनावी हलफनामे को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने उनके शपथ पत्र में दर्ज शैक्षणिक जानकारी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि उसमें शैक्षणिक योग्यता का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। विपक्ष ने मामले की जांच कराने के साथ ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की भी बात कही है। राजद विधायक रणविजय साहू का कहना है कि नीरज सिन्हा के हलफनामे में मैट्रिक और स्नातक की जानकारी दर्ज है, लेकिन इंटरमीडिएट की शैक्षणिक जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया। उनके मुताबिक, यदि कोई उम्मीदवार स्नातक की डिग्री का दावा करता है तो उससे पहले की शैक्षणिक योग्यता का पूरा विवरण भी सार्वजनिक दस्तावेज में होना चाहिए। हालांकि निर्वाचन प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है और निर्वाचन अधिकारी पहले ही नीरज सिन्हा के नामांकन को वैध घोषित कर चुके हैं।



सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सोमनाथ भारती ने साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता सतीश उपाध्याय के मालवीय नगर सीट से निर्वाचन को चुनौती दी है। उपाध्याय ने सोमनाथ भारती को 2,131 वोटों से हराया था। इस नतीजे को सोमनाथ भारती ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से याचिका खारिज होने के बाद अब सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने सोमनाथ भारती की याचिका सुनवाई के लिए लाई गई। जिस पर पीठ ने याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी। सोमनाथ भारती ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सतीश उपाध्याय ने चुनाव के दौरान प्रतिनिधि कानून 1951 का उल्लंघन किया और उनके एजेंटों द्वारा कार के जरिए लोगों को पोलिंग बूथ पर लाया गया।



पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक को दिया समर्थन

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर हो रहे उनके विरोध-प्रदर्शन के प्रति अपना समर्थन जताया। सीजेपी पिछले 25 दिनों से ज़रदा समय से विरोध-प्रदर्शन कर रही है। वे पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे और तब से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे थे। कांग्रेस ने पहले वांगचुक से उनकी सेहत को लेकर चिंता जताते हुए भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। खेड़ा का यह दौरा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव के विरोध स्थल पर वांगचुक और अन्य प्रदर्शनकारियों से मिलने के एक दिन बाद हुआ। यादव ने केंद्र से मांग की कि वह वांगचुक से बातचीत करे और सीजेपी की मांगों पर ध्यान दे।



बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों का अभेद्य कवच बनेगा भारत

कातिलाल मांडेठ

भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा देश की आर्थिक प्रगति, सामरिक शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। समुद्री मार्गों से देश का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, इसलिए बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सबसे महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में समुद्री रास्तों के जरिए आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की हेराफेरी और अवैध घुसपैठ की घटनाओं ने यह साबित किया है कि यदि समुद्री सीमाओं को निगरानी कमजोर हो तो उसका सीधा असर देश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता है। इसी चुनौती को देखते हुए केंद्र

सरकार ने अब तटीय सुरक्षा को पूरी तरह अभेद्य बनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की तटीय सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा है कि समुद्री सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने तटीय जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों के मछली बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटरों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। इन संवेदनशील स्थानों पर केवल स्थानीय पुलिसकर्मियों की तैनाती करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में निरंतरता और जवाबदेही बनी रहे। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो में केवल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से प्रशिक्षित निजी

सुरक्षा कर्मियों को ही तैनात किया जाए। इसके साथ ही सभी प्रमुख बंदरगाहों पर कंटेनर स्कैनिंग की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत के सामने उनके मुताबिक, यदि कोई उम्मीदवार स्नातक की डिग्री का दावा करता है तो उससे पहले की शैक्षणिक योग्यता का पूरा विवरण भी सार्वजनिक दस्तावेज में होना चाहिए। हालांकि निर्वाचन प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है और निर्वाचन अधिकारी पहले ही नीरज सिन्हा के नामांकन को वैध घोषित कर चुके हैं।



किया है कि समुद्री मार्गों का उपयोग आतंकवादी संगठन भी कर चुके हैं। ऐसे अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया कि तटीय सुरक्षा केवल सीमा सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली रक्षा पंक्ति है। गृह मंत्रालय की मानना है कि यदि बंदरगाहों, मछली लैंडिंग केंद्रों और समुद्री गतिविधियों पर चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखी जाए तो आतंकवादी किसी भी रूप में भारत

में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आधुनिक निगरानी प्रणाली, प्रशिक्षित सुरक्षा बल और बेहतर समन्वय आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करेंगे। समुद्री मार्गों के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी भी लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती रही है। अंतरराष्ट्रीय तस्कर समुद्री रास्तों का उपयोग करके करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ भारत तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कई बार कंटेनरों के भीतर छिपाकर प्रतिबंधित सामग्री भेजी जाती है। ऐसे मामलों में यदि प्रत्येक कंटेनर की आधुनिक स्कैनिंग होगी तो अवैध सामान की पहचान करना कहीं अधिक आसान हो जाएगा। इससे न केवल मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगेगी बल्कि हथियारों, विस्फोटकों और अन्य प्रतिबंधित

वस्तुओं की हेराफेरी भी रोकी जा सकेगी। बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था में निजी सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल लाइसेंस प्राप्त और प्रशिक्षित सुरक्षा एजेंसियों को ही यह ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। इससे सुरक्षा मानकों में एकरूपता आएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता की संभावना कम होगी। सीआईएसएफ से प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का निर्णय भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि यह बल देश के सबसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का व्यापक अनुभव रखता है।

तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए केवल पुलिस या सुरक्षा बलों की भूमिका ही पर्याप्त नहीं होती। इसमें तटरक्षक बल, नौसेना, राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियां, बंदरगाह प्राधिकरण और स्थानीय मछुआरा समुदाय सभी की सहभागिता आवश्यक होती है। समुद्र में सबसे पहले किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी अक्सर मछुआरों को मिलती है। यदि उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए तो सुरक्षा एजेंसियां समय रहते किसी भी खतरे को रोक सकती हैं। भारत वैश्विक व्यापार का तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। देश के बंदरगाहों पर प्रतिदिन हजारों कंटेनरों का आवागमन होता है। ऐसे में सुरक्षा और व्यापार के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। आधुनिक कंटेनर स्कैनिंग प्रणाली इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी क्योंकि इससे व्यापार प्रभावित किए बिना सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकेगा।

मर्तापी के जंगल से 3 किलो का प्रेशर कुकर आईईडी बरामद

उत्तर बस्तर के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है।

कांकेर। कांकेर जिले के मर्तापी गांव में सर्चिंग अभियान के दौरान करीब 3 किलो वजनी प्रेशर कुकर आईईडी बरामद की गई है। बीडीएस टीम ने मौके पर ही विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया। पुलिस का कहना है कि नक्सलियों ने



सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईईडी लगाया था। कांकेर थाना क्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर

ग्राम मर्तापी के जंगल-पहाड़ी इलाके में डीआरजी और बीडीएस की संयुक्त टीम नियमित सर्चिंग अभियान पर निकली

थी। इसी दौरान जवानों को संदिग्ध स्थान पर करीब 3 किलो वजनी प्रेशर कुकर आईईडी मिला। सूचना मिलते ही बीडीएस टीम ने पूरी सतर्कता के साथ मौके पर ही आईईडी को डिफ्यूज कर दिया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। नक्सल मुक्त होने के बाद से अबतक लगभग 40 आईईडी बरामद किया गया है, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय

किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का संयुक्त सर्चिंग अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि नक्सलियों की साजिशों को समय रहते विफल किया जा सके और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा कायम रखी जा सके। बस्तर से नक्सलवाद के ख़ात्मे का ऐलान हो गया है। उसके बाद भी नक्सलियों की साजिश का खुलासा हो रहा है। कांकेर के मर्तापी में सुरक्षा बलों ने लगातार सर्चिंग अभियान चलाकर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया।



रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि नक्सलियों द्वारा पूर्व में छिपाकर रखे गए हथियारों और अन्य अवैध सामग्री को बरामद कर किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

नक्सलमुक्त नारायणपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता

नारायणपुर। नारायणपुर जिले में नक्सलमुक्त क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में नारायणपुर पुलिस और 58वीं वाहिनी बीएसएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों का छुपाकर रखा गया हथियारों का डंप बरामद हुआ है। नक्सलमुक्त क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से नारायणपुर पुलिस और 58वीं वाहिनी बीएसएफ द्वारा थाना कोहकामेटा क्षेत्र में लगातार संयुक्त सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान

कच्चापाल के जंगल से हथियारों का डम्प बरामद

के दौरान सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम कच्चापाल के जंगल क्षेत्र में सर्चिंग कर रही थी।

सर्चिंग के दौरान जवानों को जंगल में संदिग्ध रूप से छिपाकर रखी गई सामग्री दिखाई दी। जब सुरक्षा बलों ने मौके की जांच की तो वहां नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया हथियारों और गोला-बारूद का डंप बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने मौके से एक 1303 रायफल, एक 1315 रायफल और एक स्थानीय निर्मित बैरल लांचर बरामद किया

है। इसके अलावा 1303 बोर के 17 जीवित कारतूस, 7 162 एमएम के 10 जीवित कारतूस और 12 बोर के 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एक खाली 1303 मैगजीन, दो कारतूस फिलर और तीन 1303 ट्रेसर रॉड भी सुरक्षा बलों के हाथ लगे हैं। नारायणपुर पुलिस और सुरक्षा बलों का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए

सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल के नाम से बनी फर्जी फेसबुक आईडी



साइबर टग लोगों को भेज रहे फ़्रेण्ड रिक्वेस्ट

सरगुजा। सरगुजा जिले में साइबर टगो का एक नया मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल के नाम और तस्वीर का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक आईडी बना ली है।

इस फर्जी प्रोफाइल के जरिए टग लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे मोबाइल नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भौगोलिकसंदर्भ मामले की जांचकारी मिलते ही एसएसपी राजेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि

संबंधित फेसबुक प्रोफाइल पूरी तरह फर्जी है और इसका उनसे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने नागरिकों से ऐसी किसी भी आईडी पर भरोसा न करने और किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है।

एसएसपी ने बताया कि इस संबंध में साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा दी गई है।

साथ ही फर्जी प्रोफाइल को हटाने के लिए मेटा कंपनी को भी सूचना भेजी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फर्जी आईडी संचालित करने वालों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

शिक्षा विभाग में वर्षों पुरानी अटैचमेंट व्यवस्था खत्म

बलरामपुर। बलरामपुर शिक्षा विभाग में लंबे समय से जड़ जमा चुकी अटैचमेंट (संलग्नता) व्यवस्था को डीईओ के आदेश के बाद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। डीपीआई से मिले सख्त निर्देशों के बाद डीईओ ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जिससे पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है।

इस आदेश के तहत व्याख्याता, शिक्षक से लेकर श्रृंख तक, जो भी कर्मचारी अपनी मूल शालाओं को छोड़कर अन्य जगहों पर अटैच थे, उन्हें सामूहिक रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया है। साथ

ही सभी कर्मचारियों को मूल पदस्थापना पर लौटने के निर्देश भी दे दिए हैं। इस कार्रवाई के बीच कुछ विभागों और पदों को लेकर अब भी संशय की स्थिति बनी हुई है। आदेश में मंडल संयोजक, एकलव्य एवं प्रयास विद्यालय के कर्मचारी और छात्रावास अधीक्षक को कार्यमुक्त नहीं किया गया है। इन पदों पर काम कर रहे अधिकारी-कर्मचारी फिलहाल इस आदेश के दायरे से बाहर हैं। फिलहाल, सभी की निगाहें विभाग के अगले आदेश पर टिकी हुई हैं।

एसपी दफ्तर के सामने हार्ड-वोल्टेज ड्रामा, युवक अरेस्ट



रायगढ़। शहर के पुलिस अधीक्षक (स्कू) कार्यालय के सामने आज नामी बदमाश चाहत शुक्ला ने जमकर हंगामा किया। उसने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सुखनंदन पटेल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। हंगामे के कुछ ही देर बाद कोतवाली पुलिस ने मुत्सैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शहर में उसका पैदल मार्च निकालते हुए न्यायालय में पेश किया एसपी कार्यालय के सामने हंगामा करते हुए चाहत शुक्ला ने आरोप लगाया कि सिटी कोतवाली प्रभारी सुखनंदन पटेल

राजनैतिक सपोर्ट पर काम कर रहे हैं। उसने सनसनीखेज दावा किया कि वह वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के रिश्तेदार होने का फायदा उठा रहे हैं और इसी के चलते उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दो बार जिला बदर

होने के बाद अदालत से बरी होने पर चाहत ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हंगामे के बाद कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पैदल मार्च कराते हुए न्यायालय में पेश किया।

बिस्तर पर पड़े पिता को उतारा मौत के घाट, फिर मां को मारने पहुंचा बहन के घर, आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर। जो बेटा पिता के बुढ़ापे का सहारा बनता उसी ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नवागांव (गिरजाबंद) में बीती रात हुई। नशे में धुत एक युवक ने अपने लकवाग्रस्त और बिस्तर पर पड़े 65 वर्षीय पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पिता की हत्या के बाद वह अपनी मां को भी मारने के इरादे से बहन के घर पहुंच गया।

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निलेश पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस घटना की जांच में जुटी है। दरअसल, मृतक रिखी राम सूर्यवंशी (65 वर्ष) लंबे समय से पैरालिसिस से पीड़ित थे और बिस्तर पर ही रहते थे। आरोपी उनका बेटा शिवचरण सूर्यवंशी नशे में आएं दिन अपने पिता-पिता के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करता था। गुरुवार रात करीब 11 बजे वह नशे की



हालत में घर पहुंचा। बेटे के आक्रामक व्यवहार को देखते हुए रिखी राम ने अपनी पत्नी को पास में रहने वाली बेटी के घर भेज दिया, क्योंकि आरोपी अक्सर दोनों के साथ मारपीट करता था। इसके बाद घर में मौजूद लकवाग्रस्त पिता पर आरोपी बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि पड़े-पड़े बड़बड़ाता रहता है कहते हुए उसने डंडे से पिता के सिर पर लगातार वार किए। गंभीर चोटों के कारण रिखी राम सूर्यवंशी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पिता की हत्या के बाद भी आरोपी का गुस्सा शांत नहीं

हुआ। वह अपनी मां को मारने के इरादे से बहन के घर पहुंच गया। परिजनों ने दरवाजा बंद कर लिया तो आरोपी उसे तोड़ने का प्रयास करने लगा। इसी बीच पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही रतनपुर थाना प्रभारी निलेश पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया। एफएसएल टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, ननि की खुली पोल

बिलासपुर। बिलासपुर में हो रही बारिश ने बिलासपुर नगर निगम की तैयारियों और शहर की जल निकासी व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी। कुछ ही घंटों की बारिश में शहर के कई इलाकों की सड़कें, गली-मोहल्ले और निचले क्षेत्र जलमग्न हो गए, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बिलासपुर में हो रही बारिश ने बिलासपुर नगर निगम की तैयारियों और शहर की जल निकासी व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी। कुछ ही घंटों की बारिश में शहर के कई इलाकों की सड़कें, गली-मोहल्ले और निचले क्षेत्र जलमग्न हो गए, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे घरेलू सामान खराब होने के साथ लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वही सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सिरगिट्टी का वार्ड क्रमांक 12 शामिल रहा, जहां दर्जनों कच्चे मिट्टी के घरों में पानी भर गया। घरों में पानी घुसने से परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की नौबत आ गई।

मवेशी तस्करी के खिलाफ सूरजपुर पुलिस का एक्शन

सूरजपुर। मवेशियों को पैदल जंगल के रास्ते जिले की सीमा पार कराने की कोशिश की जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर कार्रवाई की, लेकिन अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर तस्करी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी मवेशियों को सुरक्षित कब्जे में लेकर गांव के सरपंच की सुपुर्दगी में रखा है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चंदौरा थाना और रेवटी चौकी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मवेशियों की तस्करी किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर चंदौरा थाना और रेवटी चौकी की संयुक्त पुलिस टीम ने जंगल के रास्तों में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने छोटे-बड़े कुल 63 गौवंशों को बरामद किया, जिन्हें तत्कर पैदल हांककर सीमा पार ले जा रहे थे। पुलिस को देखते ही तत्कर मवेशियों को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस ने सभी गौवंशों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर गांव के सरपंच की सुपुर्दगी में सौंप दिया है, ताकि उनकी उचित देखभाल की जा सके।

अम्बिकापुर में महिला के गले से चेन लूटकर भागे बाइकर्स

सरगुजा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर सहायक संचालक पूनम तिवारी के गले से बाइकर्स बदमाश सोने का चेन लूटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पूनम तिवारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हैं। पूनम तिवारी दोपहर में लंच के लिए घर गई थीं। दोपहर को जब स्कूटी से वापस जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचीं। स्कूटी खड़ी करने के बाद जैसे ही वे पैदल कार्यालय की ओर बढ़ीं, उसी समय बाइक सवार दो युवक उनके पास पहुंचे। बदमाशों ने बाइक की रफ्तार धीमी की और पूनम तिवारी के गले से सोने की चेन झपट ली। घटना इतनी तेजी से हुई कि वे कुछ समझ पातीं, उससे पहले ही दोनों आरोपी गुरुनानक चौक की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोतवाली थाना और सीएसपी कार्यालय के ठीक सामने स्थित है।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान विक्रय हेतु एग्रीस्टेक पंजी जरूरी

कोंडगांव। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान विक्रय एवं शासन की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों से समय पर एग्रीस्टेक पंजीयन कराने की अपील की गई है। पंजीयन के लिए किसानों को आधार से लिंक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड तथा आवश्यक भूमि संबंधी दस्तावेजों के साथ अपने निकटस्थ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति अथवा पंजीयन केंद्र में संपर्क करना होगा। जिन किसानों का पंजीयन पहले से है, वे भी अपने रकबे, फसल एवं अन्य विवरण का सत्यापन एवं आवश्यक संशोधन समय पर अवश्य करा लें। विभाग द्वारा किसानों को बताया गया है कि नवीन किसान, बंटाईदार, वनाधिकार पट्टाधारी तथा अन्य पात्र कृषक भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के दौरान बैंक खाता, आधार एवं अन्य आवश्यक जानकारीयां सही एवं अद्यतन होना आवश्यक है। धान विक्रय के समय आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य रहेगा।

सेवा सेतु पोर्टल से मुकुटा को मिला नया राशन कार्ड

महासमुंद्र। सेवा सेतु पोर्टल आम नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में बसना विकासखंड के ग्राम पंचायत गनेकेरा निवासी श्रीमती मुकुटा, पति लोकनाथ को सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नया राशन कार्ड सहजता से प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत गनेकेरा के मनीष सोनी ने श्रीमती मुकुटा के राशन कार्ड के लिए सेवा सेतु पोर्टल पर आवेदन किया था। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उनका राशन कार्ड आसानी से बन गया। राशन कार्ड मिलने से श्रीमती मुकुटा ने खुशी व्यक्त करते हुए शासन और प्रशासन का आभार जताया। जिला तकनीकी प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। पोर्टल की प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल है। इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

धमतरी को मिली हाईटेक वेंटिलेटर एम्बुलेंस की सौगात

धमतरी। भगवान श्री जगन्नाथ रथयात्रा के पावन अवसर पर धमतरीवासियों को एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधा की सौगात मिली। समाजसेवी के सहयोग से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस श्याम रथ बहु-प्रशिक्षित वेंटिलेटर एम्बुलेंस का शुभारंभ श्री राष्ट्रीय गौशाला, जनकपुर में वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर किया गया।

समाजसेवियों ने बताया कि धमतरी में लंबे समय से अत्याधुनिक वेंटिलेटर एम्बुलेंस की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर से महंे



किराए पर वेंटिलेटर एम्बुलेंस बुलानी पड़ती थी, जिससे समय और धन दोनों की बड़ी समस्या होती थी। अब यह परेशानी काफी हद तक दूर हो जाएगी।

करीब 30 लाख रुपये की लागत से तैयार इस हाईटेक एम्बुलेंस में वे सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो बड़े शहरों में संचालित



एडवांस लाइफ सपोर्ट (८२) एम्बुलेंस में होती हैं। इसमें वेंटिलेटर, अत्याधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम सहित छोटे बच्चों के इलाज और सुरक्षित परिवहन के

लिए भी विशेष चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। समाजसेवियों ने बताया कि श्याम रथ धमतरी जिले के लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। किसी भी गंभीर मरीज को अस्पताल तक सुरक्षित और त्वरित पहुंचाने में यह एम्बुलेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनका कहना है कि समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने से कई मरीजों की जान बचाई जा सकेगी।

शुभारंभ के दौरान उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे धमतरी के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

मासूम की मौत के बाद हरकत में आया नगर निगम

दादर में पकड़े 20 कुत्ते, पीड़ित परिवार को 1 लाख की साखयता

कोरबा। कोरबा में दादर में आवारा कुत्तों के हमले से 5 साल के मासूम प्रकाश पटेल की दर्दनाक मौत के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया। शुक्रवार को निगम आयुक्त आशुतोष पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद दादर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू किया गया। आयुक्त आशुतोष पांडे ने दादर पहुंचकर स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों की तुरंत धर-पकड़ की जाए। आयुक्त ने कहा कि इस तरह की घटना बेहद दुखद है और इसे रोकने के लिए निगम गंभीरता से काम करेगा। निगम की टीम ने दादर और आसपास के इलाकों में अभियान चलाकर 15 से 20 आवारा कुत्तों को पकड़ा। सभी कुत्तों को बंध्याकरण के लिए नगर निगम द्वारा बनाए गए सेंटर भेजा गया है।



आयुक्त ने बताया कि इससे पहले भी निगम द्वारा आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाए जा चुके हैं। निगम के बंध्याकरण सेंटर में अब तक हजार से अधिक कुत्तों का बंध्याकरण किया जा चुका है और यह प्रक्रिया आगे भी लगातार जारी रहेगी। दादर में गुरुवार को आवारा कुत्तों के झुंड ने 5 साल के मासूम प्रकाश पटेल पर हमला कर दिया था। प्रकाश अपने पिता किशोर पटेल से मिलने गया था जो वहां मजदूरी कर रहे थे। मिलने के बाद जब मासूम घर लौट रहा था तभी रास्ते में कुत्तों ने उसे दौड़ा-दौड़ाकर नोच डाला।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की पुलिस रिमांड 5 दिन बढ़ी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला और शराब घोटाला मामलों में गिरफ्तार कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। अदालत ने उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब रामगोपाल अग्रवाल 22 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) की हिरासत में रहेंगे। रामगोपाल अग्रवाल के बचाव पक्ष के वकील फैसल रिजवी ने रिमांड बढ़ाए जाने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए अदालत से 5 दिन की अतिरिक्त रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले रामगोपाल 9 दिनों तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर थे। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को पहले कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में वह 9 दिन की पुलिस रिमांड पर थे। इसी दौरान ईओडब्ल्यू ने उन्हें शराब घोटाला मामले में भी गिरफ्तार किया। अब जांच एजेंसी दोनों मामलों में उनसे पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि रिमांड के दौरान ईओडब्ल्यू घोटालों से जुड़े वित्तीय लेनदेन, अन्य आरोपियों की भूमिका और दस्तावेजी साक्ष्यों के संबंध में रामगोपाल अग्रवाल से विस्तृत पूछताछ करेगी।

एम्स रायपुर में जल्द बनेगी अत्याधुनिक एडवांस्ड बर्न यूनिट

रायपुर। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर के बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा वैज्ञानिक एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण (रिकंस्ट्रक्टिव) सर्जरी की व्यापक उपयोगिता, आधुनिक उपचार पद्धतियों तथा इससे मरीजों के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम्स रायपुर के कार्यपालन निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त) ने कहा कि संस्थान का बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग जन्मजात चेहरे एवं हाथ-पैरों की विकृतियों, कटे होट एवं तालू (क्लेफ्ट लिप एवं पैलेट), जलने से होने वाली विकृतियों, दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त अंगों, नसों की चोट, सौंदर्य संबंधी समस्याओं तथा माइक्रोवैस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन जैसी जटिल शल्य चिकित्सा में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि एम्स रायपुर में शीघ्र ही अत्याधुनिक एडवांस्ड बर्न यूनिट स्थापित की जाएगी, जिससे गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को और बेहतर एवं समर्पित उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

किसानों को समय पर मिल रहे खाद-बीज, 93 प्रतिशत बीज वितरण पूरा

रायपुर। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव जिले में बीज और उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण किया गया है। अब तक 1.12 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई पूरी हो चुकी है, जबकि धान की रोपाईं और बुवाई का काम तेजी से जारी है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाए। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों की आवश्यकताओं की नियमित निगरानी की जाए और समय पर सामग्री उपलब्ध कराई जाए। जिले में खरीफ 2026 के लिए 14,331 क्विंटल बीज की मांग के विरुद्ध 14,686 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 102 प्रतिशत है। इनमें से 13,700.82 क्विंटल बीज का वितरण सहकारी समितियों एवं कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को किया जा चुका है। यह कुल भंडारण का 93 प्रतिशत है। खरीफ फसलों की बुवाई भी संतोषजनक गति से जारी है। अब तक जिले में 1,12,884.92 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई पूरी हो चुकी है। इसमें सर्वाधिक 1,11,339 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुवाई एवं रोपाई का कार्य संपन्न हुआ है।

नकटी मामले में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रभावितो के साथ राज्यपाल से मिला

रायपुर। नकटी तोड़-फोड़ मामले में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल प्रभावित ग्रामीणो के प्रतिनिधियो के साथ राज्यपाल से मिलकर जापान सौंपा।

जापान में कहा गया कि जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी, रायपुर की ओर से आपका ध्यान ग्राम नकटी में घटित अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक घटना की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं, विदित है कि दिनांक 29-30 जून 2026 को रायपुर जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम-नकटी (सम्मानपुर) माना क्षेत्र में लगभग 85 से अधिक आवासों पर बेदखली एवं विध्वंस की कार्यवाही की गयी, जिसमें अनेक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास स्वीकृत किये गये। इस घटना ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। यदि समयबद्ध, निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्रवाई नहीं होती है, तो आम जनता का कानून एवं संविधान पर विश्वास कमजोर होगा।

जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी का तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर मामना है कि प्रत्येक नागरिक के जीवन,



सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, पक्षपात अथवा दोषियों को संरक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत घातक है। अतः इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

कांग्रेस की मांगें निम्नानुसार हैं-

- ग्राम नकटी प्रकरण की न्यायिक आयोग अथवा स्वतंत्र उच्चस्तरीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए।

- घटना में संलिप्त सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

‘महतारी वंदन’ पर सदन में मचा हंगामा

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने किया किया वॉकआउट



रायपुर। साय सरकार की महत्वकांक्षी महतारी वंदन योजना के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप सदन में लगा। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने मुद्दा उठाते हुए पोर्टल नहीं खुलने की बात कही। इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सुशासन की सरकार का हवाला देते हुए सीख नहीं देने की नसीहत दे डाली। विपक्ष ने यह सुनते ही सदन में हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी करते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।

कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सदन में मंत्री से सवाल पूछा कि कितनी पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ जून 26 तक मिला? जिनको नहीं मिला उसकी वजह क्या है? इस पर मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने बताया कि प्रारंभ में कुल 70,27,154 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से पात्र 70,09,658 को प्रथम भुगतान किया गया।

मंत्री ने बताया कि जून 26 की

ईकेवाईसी बाकी है। 55,000 महिलाओं को काटा है। तो 1 लाख लोग बचे हैं। इस पर मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि 1,23,000 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। इस पर उमेश पटेल ने पूछा मार्च 24 से पोर्टल नहीं खुला है। यह कब तक खुलेगा?

इस पर मंत्री ने कहा कि सुशासन की सरकार है। हमने सरकार बनते ही 2 महीने में पैसा दे दिया आप न सिखाएँ। इसके साथ ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। इसके साथ महतारी वंदन योजना के कारण 2% महिलाओं का महतारी वंदन का पैसा रुका है।

इस पर उमेश पटेल ने कहा कि मैं

महीने में 36000 महिलाओं का



प्रदेश की जनता के नाम संदेश देंगे।

जिला मुख्यालयों में शासन द्वारा नामित मंत्री ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। यहाँ स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जनपद पंचायत मुख्यालयों में जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिकाओं व पंचायतों में उनके अध्यक्ष व सरपंच तथा बड़े गांवों में ग्राम प्रमुख ध्वजारोहण करेंगे। इन स्थलों पर राष्ट्रीय गान, भाषण देश देश की एकता एवं अखंडता का संदेश प्रसारित किया जाएगा। जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि जिला स्तरीय समारोह में स्वतंत्रता

सरोना रेलवे स्टेशन: आधुनिक रेल अवसंरचना के साथ क्षेत्रीय विकास की नई पहचान



एवं विश्वसनिय बन रहा है।

सरोना रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निकट स्थित एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह स्टेशन रायपुर शहर, औद्योगिक क्षेत्रों तथा आसपास के तेजी से विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्रों के यात्रियों के लिए सुविधाजनक के अंतर्गत सरोना रेलवे स्टेशन का यह रेल संपर्क उपलब्ध कराता है। साथ ही, रायपुर आने वाले पर्यटकों एवं व्यापारिक यात्रियों के लिए भी यह स्टेशन एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु है। स्टेशन के आधुनिकीकरण से क्षेत्रीय आवागमन, व्यापारिक गतिविधियों तथा रोजगार के अवसरों को नई गति मिलेगी।

सरोना रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों के अंतर्गत 95 वर्गमीटर का नया

कॉनकोर्स भवन, लगभग 2000 वर्गमीटर का विकसित सर्कुलेटिंग एरिया, नया फुट ओवर ब्रिज, सात प्लेटफॉर्म शेल्टर, 2,800 वर्गमीटर प्लेटफॉर्म सरफेसिंग का उन्नयन, 2 लिफ्ट, आधुनिक प्रतीक्षालय, उन्नत शौचालय, द्वितीय प्रवेश द्वार, समुचित और पर्याप्त पार्किंग स्थान, एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे तथा आकर्षक कला एवं सांस्कृतिक सज्जा विकसित की गई है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए बैटने की पर्याप्त व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। अमृत प्रभार स्टेशन योजना के अंतर्गत सरोना रेलवे स्टेशन का यह कार्याकल्प न केवल यात्रियों को आधुनिक एवं विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा, बल्कि रायपुर महानगर एवं आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। यह पुनर्विकास कार्य भारतीय रेल की यात्रा-केंद्रित, सुरक्षित एवं सतत् विकास की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है।

विधानसभा मानसून सत्र : राशन दुकानों में बेचा जा रहा मसाला!

■ विधायक सुशांत शुक्ला के आरोप पर मंत्री बघेल ने की जांच कराने की घोषणा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन दुकानों के जरिए मसाला बेचने का आरोप लगाया। मंत्री दयाल दास बघेल के जानकारी नहीं होने बात कहने पर विधायक ने दस्तावेज हाथ में होने की बात कही। इस पर मंत्री बघेल ने दस्तावेज दिए जाने पर जांच कराने का आश्वासन दिलाया।

भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने अपने सवाल की शुरुआत राशन दुकानों के बचत स्टॉक के सत्यापन से की। उन्होंने आरोप लगाया कि जानकारी छिपाई जा रही है। अप्रैल 2025 तक की जानकारी दिए जाने की बात कहते हुए विधायक ने सवाल किया कि आखिर क्यों पूरी जानकारी छिपाई जा रही है? इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि हमने जांच कराई है। अधिकारी लगातार एक-एक दुकानों का जांच करते हैं। शिकायत सामने आने पर कार्यवाही भी की गई है।

इस पर विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि



कौन-कौन से राशन आम जानों को उचित मूल्य के तहत दिया जाता है? उसका मॉनेटिंग कौन कर रहा है? मंत्री ने बताया कि अधिकारी हर 15 दिन में निरीक्षण करते रहते है। इस निरीक्षण भौतिक सत्यापन में जो शिकायत मिली है, उस पर कार्यवाही भी की गई है। राशन दुकान में चावल, शकर देते हैं। बस्तर में चना भी दिया जाता है।

विधायक अपना सवाल जारी रखते हुए पूछा कि क्या राशन दुकानों में मसालों की भी बिक्री की कोई व्यवस्था की गई है? मंत्री के इंकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि जानकारी इसलिए नहीं दी जा रही है, क्योंकि महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाओं पर दबाव बनाकर मसाला की बिक्री करवाई जा रही है। इसमें जांच की घोषणा कर दें। दस्तावेज मैं उपलब्ध करा दूंगा। मेरे हाथ में दस्तावेज है। इस पर मंत्री ने कहा कि जो भी दस्तावेज है आप दें दें, जांच करवा देंगे।

बलौदाबाजार हिंसा मामला : जेल से बाहर आएंगे अमित बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में स्ट न बघेल को जमानत दे दी है। सह-आरोपी अजय यादव और दिनेश वर्मा को भी राहत मिली है। इससे पहले रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा खंडित होने के दौरान सिंधी समाज के आराध्य के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वाले मामले में भी अमित बघेल को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी बी सुरेश और अधिवक्ता हर्षवर्धन परमानिहा ने पेरवी की। बचाव पक्ष के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार

ठेकेदारों का हल्लाबोल: दो साल से लंबित भुगतान को लेकर विधानसभा घेराव करने निकले

रायपुर। लंबित भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कांटेक्टर एसोसिएशन ने विधानसभा घेराव के लिए मार्च निकाला। बड़ी संख्या में पहुंचे ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई ठेकेदारों ने अपनी शर्ट उतारकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया और सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने की कोशिश की।

प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों का भुगतान पिछले दो वर्षों से लंबित है। उनका आरोप है कि समय पर भुगतान नहीं मिलने के कारण वे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। मजदूरों का भुगतान,

सामग्री सप्लायरों का बकाया और बैंक की किस्तें चुकाना मुश्किल हो गया है। ठेकेदारों ने मांग की कि सरकार कार्य की प्रगति के अनुसार किस्तों में भुगतान की व्यवस्था लागू करे, ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हो और ठेकेदारों पर आर्थिक बोझ कम हो। उनका कहना है कि भुगतान में लगातार हो रही देरी से कई परियोजनाओं की गति भी प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे। विधानसभा घेराव को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता				
लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर				
(केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ) ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना				
Main Portal: https:// eproc.cgstate.gov.in				
निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:-				
स.क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक / दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित अनुमानित लागत (रु.लाख में)	
1	195268 प्रथम आमंत्रण 10.07.2026	जिला रायपुर के खारून रिवर फ्रंट के निर्माण विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य, विद्युतीकरण कार्य सहित। संभाग क्रमांक 1 रायपुर।	6133.96	
2	195351 प्रथम आमंत्रण 13.07.2026	जिला बलरामपुर रामनृजरांग के स्याही सनावल मार्ग के कि.मी. 01 से 09, 13 से 18 एवं 23 से 35 कि.मी. कुल 28.00 कि.मी. मजबूतीकरण एवं उन्नयन कार्य।	910.48	
3	195347 प्रथम आमंत्रण 13.07.2026	1. जिला जशपुर के रापाडाड केरसई से राहेंटोलो मार्ग लं. 1.74 कि.मी. का निर्माण कार्य। 2. जिला जशपुर के मुख्य मार्ग सिंगीबहार से राहेंटुण्डा तक मार्ग लंबाई 0.94 कि.मी. निर्माण कार्य।	308.08	
4	195368 द्वितीय आमंत्रण 13.07.2026	जिला गरियाबंद अंतर्गत व्यवहार न्यायालय गरियाबंद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु 02 नग एफ, 15 नाग की, 20 नाग एच एवं 15 नाग आई टाइप शासकीय आवास गृह का निर्माण तथा पहुंच मार्ग, नाली, गार्डन, कांड कैचर, ओवर हेड टैंक, बाइपासवांल निर्माण कार्य, विद्युतीकरण सहित।	840.67	
5	195374 आठवां आमंत्रण 13.07.2026	जिला दत्तेबाड़ा के कुराम समेली मार्ग के कि.मी. 3/6 मलंगर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	367.10	
6	195376 द्वितीय आमंत्रण 13.07.2026	जिला रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर छ.ग. में अतिरिक्त मरम्मत, नवीनीकरण, जीर्णोधार फसाड लाईटिंग उन्नयन कार्य एवं अतिरिक्त रनोवेशन कार्य, विद्युतीकरण सहित (जमा मद का कार्य)।	3023.93	
7	195375 द्वितीय आमंत्रण 13.07.2026	जिला कोरकर के मुख्य मार्ग कोकर भातुप्रतापपुर संबलपुर मार्ग से मिन्चीपाता मार्ग लंबाई 2.15 कि.मी. का पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य।	314.71	
8	195369 छठवां आमंत्रण 13.07.2026	जिला कोरबा के लेमरू श्याम मार्ग में लमटी नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	370.64	
9	195362 तृतीय आमंत्रण 13.07.2026	जगदलपुर केन्द्रीय जेल में 06 नाग बैरक (फैम्ट्री बैरक (जी.एफ./एफ. एफ. एण्ड II एफ. हाईसेल बैरक) (शेष कार्य) विद्युतीकरण सहित।	241.19	
10	195359 द्वितीय आमंत्रण 13.07.2026	अण्डी किरकार जगमदन से सातबहीनिया तक मार्ग लंबाई 5.30 कि.मी. का निर्माण कार्य।	762.48	
11	195363 द्वितीय आमंत्रण 13.07.2026	वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल जिला कोण्डागांव के चांदबेड़ा (छोटियामुड़ा से छिंदली) तक मार्ग लंबाई 3.375 कि.मी. पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य।	405.19	
12	195383 द्वितीय आमंत्रण 13.07.2026	जिला कोरिया के केन्दई बरदर बैकुण्ठपुर सोनहत रामगढ़ म.प्र. सीमा मार्ग लं. 20.46 कि.मी. का मजबूतीकरण निर्माण कार्य	1529.38	
13	195349 प्रथम आमंत्रण 13.07.2026	जिला सूरजपुर के भंवरखोह से गंगपुर करीं कृपा तक पहुंच मार्ग लं. 5.10 कि.मी. पुल पुलिया सहित मार्ग निर्माण कार्य।	697.94	
निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि स.क्र. 01 दिनांक 03.08.2026, स.क्र. 02 से स.क्र. 03, स.क्र. 13 दिनांक 05.08.2026, स.क्र. 05, स.क्र. 08 से स.क्र. 09 दिनांक 27.07.2026 निर्धारित है। एवं अन्य शेष निविदाओं के लिए दिनांक 31.07.2026 निर्धारित है। निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाइट में देखे जा सकते है।				
मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियंता, कार्यालय निविदा अभियंता, नवा रायपुर, अटल नगर				
जी-262702148/10				

फिलिस्तीन के लिए भारत का समर्थन और रणनीतिक संदेश

अरुणिम भूयान

फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) के तहत फिलिस्तीन के लिए नए मानवीय और विकास परियोजनाओं की भारत की घोषणा, पुनर्विकास में मदद से कहीं ज्यादा महत्व रखती है।

ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद और ऐसे समय में जब गाजा एक पहले कभी नहीं हुए मानवीय संकट से जूझ रहा है, यह कदम पश्चिम एशिया में एक-दूसरे के हितों को संतुलित करने की नई दिल्ली की बड़ी रणनीति को दिखाता है – इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध और मजबूत करना, अरब देशों के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखना, और बहुपक्षीय संस्थानों के जरिये फिलिस्तीनी उद्देश्य के लिए अपने लंबे समय से चले आ रहे समर्थन की फिर से पुष्टि करना।

विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, सोमवार को बेल्वियम की राजधानी ब्रसेल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मॉनिस्टरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत फिलिस्तीनी लोगों का

लंबे समय से साझेदार रहा है, और उन्होंने दो-राष्ट्र समाधान के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता के लिए भारत के लगातार समर्थन को फिर से दोहराया।

बयान में कहा गया है, उन्होंने (श्रीप्रिया रंगनाथन ने) भारत की चल रही विकास-संबंधी मदद पर जोर दिया, जिसमें क्षमता निर्माण कार्यक्रम और फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय मदद शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत की परियोजनाएं मांग पर आधारित हैं और ज्यादातर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, क्षमता निर्माण और वोकेशनल ट्रेनिंग पर केंद्रित हैं।

उन्होंने कहा, यह कहते हुए कि भारत अभी फिलिस्तीन में स्वास्थ्य देखभाल, महिला संश्लिकरण और संस्थानों के पुनर्विकास के बड़े प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है, उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग पर केंद्रित कई नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की।

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि रंगनाथन ने UNRWA के सलाहकार आयोग के आगामी अध्यक्ष के रूप में बेल्वियम द्वारा आयोजित एक बैठक में भी भाग लिया, जिसके दौरान उन्होंने एजेंसी और फिलिस्तीन में इसके प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन पर प्रकाश डाला।



इस बीच, न्यूयॉर्क में 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के अभियान लॉन्च पर बोलते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने फिलिस्तीन के लिए एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक आर्टिफिशियल लिंब फिटमेंट सेंटर और एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का भी वादा किया है। जयशंकर ने कहा, यह दो-राष्ट्र समाधान के लिए हमारे लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के अनुरूप है।

मंगलवार को नई दिल्ली में नियमित मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ब्रसेल्स में हुई बैठक के दौरान भारत ने फिलिस्तीन का लंबे समय से विकास साझेदार बने रहने का अपना वादा दोहराया। जायसवाल ने कहा, हम अपनी

विकास परियोजनाओं और UNRWA के जरिये भी, फिलिस्तीनी लोगों के लिए और ज्यादा करना चाहते हैं। हम UNRWA में योगदान दे रहे हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। यह खास बैठक यूरोपीय आयोग और फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने आयोजित की थी।

भारत की नीति में बदलाव दिखाने के बजाय, ब्रसेल्स और न्यूयॉर्क दोनों जगह की घोषणाएं, इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने के नई दिल्ली के लंबे समय से चले आ रहे नजरिये को और मजबूत करती हैं, साथ ही विकास में मदद के जरिये फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करती हैं और दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करती हैं।

भारत ने इजराइल के बनने से पहले से ही फिलिस्तीनी स्वाधीनता का लगातार समर्थन किया है। हालांकि 1990 के दशक से इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते काफी गहरे हुए हैं – खासकर रक्षा, कृषि, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में डूब फिर भी भारत ने कभी भी आधिकारिक रूप से दो-राष्ट्र नीति के लिए अपना समर्थन नहीं छोड़ा है।

ब्रसेल्स में रंगनाथन के बयान ने भारतीय नीति के तीन पुराने स्तंभों की फिर से पुष्टि की- बातचीत से दो-देशों के समाधान के लिए

समर्थन, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता के लिए समर्थन, और लगातार विकास और मानवीय मदद। हेल्थकेयर, शिक्षा, पुनर्वास, वोकेशनल ट्रेनिंग और महिला सशक्तीकरण में नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा नीति में बदलाव के बजाय नीति में निरंतरता दिखाती है। यह घोषणा बहुत ही नाजुक समय पर हुई है।

ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान ने पश्चिम एशिया के रणनीतिक माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। इसने ग्लोबल साउथ में लंबे समय तक चलने वाले क्षेत्रीय विवादों की मानवीय कीमत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस पृष्ठभूमि में, UNRWA के साथ भारत का नया जुड़ाव कई कूटनीतिक संदेश भेजता है। भारत ने पिछले दशक में इजराइल के साथ रक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाया है। लेकिन, इलाके के झगड़े के बीच फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए और मदद का ऐलान करके, नई दिल्ली ने दिखाया कि इजराइल के साथ रणनीतिक संबंधों का मतलब यह नहीं है कि फिलिस्तीनी मानवीय चिंताओं को छोड़ दिया जाए।

नई दिल्ली ने संकेत दिया है कि भारत द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और मानवीय

जिम्मेदारियों के बीच अंतर करना जारी रखता है। यह भारत के गुट की राजनीति के बजाय मुद्दों पर आधारित साझेदारी बनाए रखने के बड़े सिद्धांत को दिखाता है। UNRWA सबसे अधिक राजनीतिक रूप से विवादित यूएन एजेंसियों में से एक बन गई है।

इजराइल ने बार-बार UNRWA के कुछ लोगों पर हमاس से संबंध होने का आरोप लगाया है और एजेंसी के ऑपरेशन को कम करने की कोशिश की है। कई पश्चिमी देशों ने इन आरोपों की जांच के दौरान कुछ समय के लिए फंडिंग रोक दी थी, लेकिन समीक्षा और अतिरिक्त निगरानी उपायों के बाद कई देशों ने फिर से योगदान शुरू कर दिया।

UNRWA के लिए अपना समर्थन दोहराकर, भारत ने बहुपक्षीय मानवीय सिस्टम में भरोसा दिखाया है, और साथ ही किसी भी पक्ष की राजनीतिक बातों का समर्थन करने से भी परहेज किया है। यह भारत की व्यापक विदेश नीति के अनुरूप है, जिसमें बहुपक्षीय संस्थाओं को बदलने के बजाय उन्हें मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। 2023 में जी20 की अध्यक्षता संभालने के बाद से, भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर तेजी से पेश किया है।

मंदिरों में भ्रष्टाचार : वहां सुशासन की नई क्रांति का सूत्रपात हो

ललित गर्ग

भारत की पहचान केवल उसकी प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक दर्शन से नहीं है, बल्कि उन मंदिरों से भी है जो करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और जीवन का आधार हैं। अयोध्या का श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ धाम, माता वैष्णोदेवी, तिरुपति, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, सालासर बालाजी, खादू श्यामजी जैसे मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा के जीवंत प्रतीक हैं। इन मंदिरों में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु इस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि यहां उन्हें केवल भगवान के दर्शन ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और नैतिक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। लेकिन जब इन्हीं मंदिरों से चढ़ावे की चोरी, वित्तीय अनियमितताओं, वीआईपी संस्कृति, पुजारियों अथवा कर्मचारियों के अनुचित आचरण और श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सामने आती हैं, तब केवल कोई संस्था बदनाम नहीं होती, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था घायल होती है। हाल के वर्षों में श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ और अब माता वैष्णोदेवी मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मंदिरों की व्यवस्था को केवल धार्मिक भावना के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जिस धन को श्रद्धालु भगवान का अर्पण मानकर समर्पित करते हैं, वह किसी व्यक्ति या समूह की निजी संपत्ति नहीं है। उस धन का प्रत्येक रुपया सार्वजनिक विश्वास की धरोहर है। यदि उसी में अपारदर्शिता या चोरी का संदेह पैदा हो जाए तो यह केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वास के साथ विश्वासघात है। मंदिरों में बढ़ती अव्यवस्था का दूसरा गंभीर पक्ष है-वीआईपी दर्शन संस्कृति। आज देश का सामान्य श्रद्धालु कई-कई घंटे कतार में खड़ा रहता है। वृद्ध, महिलाएं, दिव्यांग और छोटे बच्चों के पास आए परिवार कठिन परिस्थितियों में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मंत्री, विधायक, अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति पहुंचता है, सामान्य दर्शन रोक दिए जाते हैं और वीआईपी

दर्शन शुरू हो जाते हैं। आम श्रद्धालु की लाइन रोक दी जाती है, उसके दर्शन का समय बाधित होता है और उसे यह एहसास कराया जाता है कि भगवान के दरबार में भी सभी बराबर नहीं हैं। यह स्थिति भारतीय संस्कृति और धर्म की मूल भावना के विपरीत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर के समक्ष राजा और रंक में कोई भेद नहीं होता। यदि मंदिरों में भी सामाजिक और राजनीतिक विशेषाधिकार का प्रदर्शन होगा तो यह धर्म के मूल स्वरूप का अपमान है। मंदिरों को लोकतांत्रिक समानता और आध्यात्मिक समरसता का सर्वोच्च उदाहरण बना चाहिए, न कि सामाजिक असमानता का मंच। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में ‘समान मन्दिर दर्शन नीति’ लागू की जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा या अत्यंत विशिष्ट संवैधानिक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को सामान्य श्रद्धालुओं की कतार से अलग विशेष दर्शन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी कारणवश सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक हो, तब भी आम श्रद्धालुओं के दर्शन बाधित नहीं होने चाहिए। भगवान के दरबार में सबसे बड़ा वीआईपी केवल श्रद्धा होनी चाहिए, पद और सत्ता नहीं। इसी प्रकार मंदिरों की चढ़ावा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आज डिजिटल भारत का युग है, फिर भी अनेक मंदिरों में दान और चढ़ावे की पारदर्शी व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी है। प्रत्येक बड़े मंदिर में दान-पात्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, सीसीटीवी कैमरे, बारकोड आधारित सीलिंग, नियमित स्वतंत्र ऑडिट तथा प्रत्येक माह आय-व्यय का सार्वजनिक विवरण वेबसाइट और सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्रद्धालु को यह जानने का अधिकार है कि उसके द्वारा दिया गया धन कहां और किस उद्देश्य में उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन में केवल धार्मिक पहचान ही नहीं, बल्कि चरित्र, ईमानदारी और प्रशासनिक दक्षता को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंदिर प्रबंधन समितियों में ऐसे व्यक्तियों को स्थान मिले जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा निष्कलंक हो।

अभिषेक के लिए सैकड़ों कुर्बान को तैयार ममता

सत्येंद्र प्रताप सिंह

पश्चिम बंगाल की राजनीति में मदन मित्रा का ममता तृणमूल छोड़कर त्रोब्रत तृणमूल में शामिल होना महज एक और दल-बदल नहीं है। यह उस राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जिसकी आहट तृणमूल कांग्रेस के भीतर लंबे समय से सुनाई दे रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला किसी सामान्य नेता ने नहीं, बल्कि उस व्यक्ति ने लिया है जिसे वर्षों तक ममता बनर्जी की परछाईं माना जाता रहा।

पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा प्रश्न आज यह नहीं है कि कौन तृणमूल छोड़ रहा है, बल्कि यह है कि लगभग हर असंतुष्ट नेता के निशाने पर केवल एक ही नाम क्यों है- अभिषेक बनर्जी ?

विडंबना यह है कि कल तक जो नेता अभिषेक को पार्टी का भविष्य, नई पीढ़ी का चेहरा और संगठन का सेनापति बताते नहीं थकते थे, वही आज उनके नेतृत्व पर सबसे तीखे सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मंत्री मदन मित्रा हों, पार्टी छोड़ चुके अन्य नेता हों, पूर्व वी मौजूदा सांसद हों, विधायक हों या संगठन के पुराने पदाधिकारी- लगभग सभी की शिकायतों का केंद्र अभिषेक बनर्जी हैं।

तृणमूल कांग्रेस के गठन से लेकर उसके संघर्ष और सत्ता तक पहुंचने की यात्रा में मदन मित्रा उन नेताओं में रहे, जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ सड़क से लेकर विधानसभा तक राजनीतिक लड़ाई लड़ी। ऐसे नेता का सार्वजनिक रूप से यह कहना कि अभिषेक ममता बनर्जी की भी नहीं सुनते केवल व्यक्तिगत असंतोष नहीं, बल्कि पार्टी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल है।

मदन मित्रा का आरोप है कि पार्टी में निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द सिमट गई है। संगठन की राय, वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और कार्यकर्ताओं की भावनाएं अब निर्णयों में जगह नहीं पाती। उनका दावा है कि इसी कार्णशैली ने कभी 213 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक



संकट में पहुंचा दिया।

इन आरोपों को केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया कहकर खारिज करना आसान नहीं है। ममता तृणमूल के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी भी समय-समय पर अभिषेक की कार्यशैली पर सार्वजनिक सवाल उठा चुके हैं। अलग-अलग नेताओं के बयानों में एक समानता स्पष्ट दिखाई देती है- निर्णयों का अत्यधिक केंद्रीकरण, वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा और संगठन में संवाद की कमी।

इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार फेसबुक लाइव के जरिए अभिषेक बनर्जी के बचाव में खुलकर सामने आईं। उन्होंने कहा कि अभिषेक को हर समस्या का खलनायक बना देना अब एक बहाना बन गया है।

केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए ममता ने कहा कि जब अभिषेक की पत्नी डेढ़ साल के बच्चे को लेकर सीबीआई कार्यालय पहुंची थीं और अभिषेक लगातार पूछताछ का सामना कर रहे थे, तब उनके विरोधियों को उनकी पीड़ा दिखाई नहीं दी। उनका तर्क था कि यदि अभिषेक समझौते का रास्ता चुनते, तो उन्हें बहुत पहले राहत मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना।

ममता ने यह भी दावा किया कि अभिषेक के खिलाफ लगभग 50 मामले दर्ज किए गए और उन्होंने हर लड़ाई राजनीतिक तथा कानूनी स्तर पर लड़ी। इसलिए उनकी भूमिका का मूल्यांकन भी उसी संदर्भ में किया जाना चाहिए। ममता का यह बयान केवल

भतीजे के समर्थन तक सीमित नहीं था। इसके जरिए उन्होंने अपनी राजनीति का भी बचाव किया। उनका कहना था कि यदि वह स्वयं भी सेटिंग कर लेतीं, तो तृणमूल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। यह बयान केंद्र और राज्य के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक टकराव की उनकी स्थापित राजनीतिक कथा को भी आगे बढ़ाता है।

लेकिन राजनीतिक प्रश्न अब भी वहीं खड़ा है। यदि पार्टी के मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों तथा वरिष्ठ नेताओं का एक बड़ा वर्ग लगातार संगठनात्मक संकट के लिए अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, तो क्या केवल यह कह देना पर्याप्त है कि उन्हें खलनायक बनाया जा रहा है ?

किसी भी राजनीतिक दल में जब असंतोष की लगभग हर धारा एक ही नेतृत्व की ओर संकेत करने लगे, तो उसे केवल विरोधियों की साजिश या व्यक्तिगत नाराजगी मानकर टालना पर्याप्त नहीं होता। नेतृत्व का सबसे बड़ा दायित्व केवल आरोपों का प्रतिवाद करना नहीं, बल्कि संगठन के भीतर उठ रहे सवालों का राजनीतिक समाधान भी तलाशना होता है। ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभिषेक बनर्जी पर होने वाले हर राजनीतिक हमले का जवाब वह स्वयं देंगी। उनका संदेश साफ है-अभिषेक पर हमला, उनके नेतृत्व को चुनौती देने जैसा है। लेकिन राजनीति केवल नेतृत्व के बचाव से नहीं चलती, संगठन के भीतर भरोसा बनाए रखने से भी चलती है।

अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या ममता बनर्जी इस असंतोष को केवल व्यक्तिगत नाराजगी मानकर नजरअंदाज करेंगी, या इसे तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ती बेचैनी का संकेत समझेंगी। क्योंकि जब किसी राजनीतिक दल में संस्थापक नेता की सबसे पुरानी परछाइयां भी साथ छोड़ने लगें, तब संकेत केवल व्यक्तियों का नहीं, बल्कि पूरे संगठन की दिशा और भविष्य का होता है।

तेल, प्रतिबंध और बमबारी; क्या ट्रंप के पास कोई और योजना है?

डेविड ई सेंगर

ईरान के साथ शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगियों ने अपनी रणनीति बताई थी। वह यह थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य को आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा, और अमेरिका तेल के निर्यात पर लगी रोक हटा देगा, ताकि ईरान अरबों डॉलर का तेल बेच सके। ट्रंप का मानना था कि वर्षों की पाबंदियों के बाद, ईरान को तेजी से भारी कमाई और पश्चिमी देशों के बैंकों में डॉलर तक आसानी से पहुंच मिलने लगेगी। पर, शायद ऐसा नहीं है।

समझौते के एक महीने से भी कम समय में, होर्मुज से गुजर रहे तीन जहाजों पर ईरान की तरफ से हमले हुए। इसके बाद ट्रंप ने उस छूट को रद्द कर दिया, जिसके तहत ईरान तेल बेच सकता था। अमेरिका ने दो रातों में ईरान के 170 से अधिक सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। और, अब स्थायी समझौते पर बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है, जिस पर दोनों पक्षों ने 60 दिनों में बातचीत पर सहमति जताई थी। बमबारी और शुरुआती समझौते के नाकाम होने के बाद, अगर ट्रंप और उनके सहयोगियों के पास कोई ‘प्लान सी’ है, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। इसके बजाय, ऐसा लगता है कि वे तेल पर पाबंदियों और बमबारी की कार्रवाई की ओर लौट रहे हैं, जिन्हें ट्रंप विनाशकारी बताते हैं, और जिससे अब तक सिर्फ मौजूदा उलझन ही पैदा हुई है।

बुधवार को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, ‘बात बिल्कुल साफ है। अगर वे जहाजों पर गोलीबारी करते हैं, तो हम उन्हें बुरी तरह से तबाह कर देंगे।’ दूसरे शब्दों में कहें, तो लालच की नीति छोड़ दी गई है और अरब सख्ती का तरीका फिर से अपनाया जा रहा है। लेकिन, ट्रंप प्रशासन ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उसे क्यों लगता है कि आर्थिक युद्ध और बमबारी का यह मिला-जुला तरीका इस बार अलग नतीजा देगा। अनुभवों राजनयिक रिचर्ड एन हास ने कहा, ‘अमेरिका एक तरह से रणनीतिक गतिरोध में फंस गया है। दुविधा यह है कि वह जितना ज्यादा हमला करता है, ईरान भी खाड़ी क्षेत्र के तेल और ऊर्जा से जुड़े ढांचे पर उतने ही हमले करने लगता है। वहीं, अमेरिका अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि इन ठिकानों की सुरक्षा कैसे की जाए।’

ऐसा लगता है कि ईरान को तेल बेचने से फायदा उठाने देने का फैसला ट्रंप के लिए पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। अपने पहले कार्यकाल में, और कुछ समय पहले तक, वह



सखा रखाया अपनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। लेकिन, लगता है कि ट्रंप भी ईरान में मौजूद गहरे मतभेदों के बीच फंसे हुए हैं। ये मतभेद इस हफ्ते ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भी साफ तौर पर दिखाई दिए। मुख्य आवाजाही का इंतजाम करेगा, जिसके लिए सिर्फ 60 दिनों तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।’ ट्रंप और उनके सहयोगियों को लगा कि यही जहाजों की आवाजाही शुरू करने का मुख्य तरीका है और इससे ईरानियों पर जिम्मेदारी आ जाएगी। ईरानियों ने इसे तेल ले जाने वाले अहम रास्ते पर नियंत्रण करने के मौके के तौर पर देखा और जोर दिया कि जहाज उनके तट के सबसे करीब वाले रास्ते से गुजरें। आखिरकार, ईरान ने संकेत दिया है कि वह इस जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए शुल्क लेने की योजना बना रहा है। जब अमेरिकी नौसेना ने ओमान के पास एक अलग रास्ते से जहाजों को सुरक्षित ले जाना शुरू किया, तो ईरान ने कुछ जहाजों पर गोलीबारी की। अब, लॉयड्स ऑफ लंदन के अनुसार, इस जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। इसी बात से ट्रंप परेशान हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि यह समझौता ‘खत्म’ हो गया है।

नारो शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद, ट्रंप और उनके सहयोगियों ने अपने अगले कदमों के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम कहा। नाम न बताने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि प्रशासन अब भी शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, और उन्हें उम्मीद है कि ‘तकनीकी बातचीत’ जारी रहेगी। लेकिन, इसमें भी विरोधाभास है, क्योंकि तेहरान और वाशिंगटन के बीच मतभेद ‘तकनीकी’ नहीं हैं, बल्कि वे राजनीतिक हैं, और निचले स्तर के वार्ताकारों के पास उन्हें हल करने का अधिकार नहीं होगा।

एक उदाहरण परमाणु कार्यक्रम के भविष्य से जुड़ा है। जून में हुए संघर्ष विराम समझौते में सभी अहम मुद्दों पर स्थिति साफ नहीं है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या ईरान अपने परमाणु ईंधन के भंडार पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। बराक ओबामा के कार्यकाल में 2015 के एक समझौते के तहत, ईरान ने अपने तब के भंडार का 97

प्रतिशत हिस्सा सौंप दिया था। ट्रंप इस बात को लेकर बहुत संवेदनशील हैं कि उन्हें ओबामा से कम हासिल हो सकता है। लेकिन, पहला राजनीतिक संघर्ष इस सवाल पर हो सकता है कि जलडमरूमध्य पर किसका नियंत्रण होगा। इस मामले में प्रशासन को उस समझौता ज्ञापन में अस्पष्ट भाषा वाले पैराग्राफ की कीमत चुकानी पड़ रही है, जिस पर ट्रंप ने वर्साय में हस्ताक्षर किए थे। यह इसका बेहतरीन उदाहरण है कि जब दस्तावेज में मतभेदों को स्पष्ट करने के बजाय उन्हें अस्पष्ट छोड़ दिया जाता है और बाद में उनकी अलग-अलग तरह से व्याख्या की जाती है, तो क्या होता है।

समझौते के पैराग्राफ पांच में लिखा है-‘इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद, ईरान अपनी पूरी कोशिश करके वाणिज्यिक जहाजों के लिए फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक और ओमान सागर से फारस की खाड़ी तक सुरक्षित आवाजाही का इंतजाम करेगा, जिसके लिए सिर्फ 60 दिनों तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।’ ट्रंप और उनके सहयोगियों को लगा कि यही जहाजों की आवाजाही शुरू करने का मुख्य तरीका है और इससे ईरानियों पर जिम्मेदारी आ जाएगी। ईरानियों ने इसे तेल ले जाने वाले अहम रास्ते पर नियंत्रण करने के मौके के तौर पर देखा और जोर दिया कि जहाज उनके तट के सबसे करीब वाले रास्ते से गुजरें। आखिरकार, ईरान ने संकेत दिया है कि वह इस जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए शुल्क लेने की योजना बना रहा है। जब अमेरिकी नौसेना ने ओमान के पास एक अलग रास्ते से जहाजों को सुरक्षित ले जाना शुरू किया, तो ईरान ने कुछ जहाजों पर गोलीबारी की। अब, लॉयड्स ऑफ लंदन के अनुसार, इस जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। इसी बात से ट्रंप परेशान हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि यह समझौता ‘खत्म’ हो गया है।

ट्रंप के सहयोगियों का कहना है कि वह समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह समझौता कामकाज के आधार पर है और ईरान के काम इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे। इन सब बातों से ट्रंप फिर उसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां वह अप्रैल में थे, जब उन्हें पता चला था कि सैन्य ताकत से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ईरान में कई लोग किसी भी कूटनीतिक समाधान को अगले इश्काली-अमेरिकी हमले तक का समय काटने का माध्यम ही मानते हैं।

दतिया उपचुनाव से सिंधिया ने बनाई दूरी

सुरेश तिवारी

सियासी गलियारों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया दतिया उपचुनाव में क्यों सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं? भाजपा प्रत्याशी के रूप में जैसे ही आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा हुई थी सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को दतिया उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है, लेकिन इसकी अधिकृत घोषणा आज तक कहीं दिखाई नहीं दी। इतना ही नहीं न तो स्वयं सिंधिया और न ही उनका कोई समर्थक मंत्री, तिवारी के नामांकन पत्र दाखिल करते समय नजर आया। अब चुनाव प्रभारी की भी घोषणा हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा को दतिया उपचुनाव का प्रभारी बनाया है। कुशवाहा को ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया का घोर विरोधी माना जाता है। राजनीतिक जानकार अकलन कर रहे हैं कि दतिया में सिंधिया की मौजूदगी नहीं होने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान ?

प्रदेश में करीब पांच लाख सरकारी कर्मचारी अभिषेक की जमीन को खुर्द-बुर्द करने के मामले में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वन बल प्रमुख शुभ रंजन सेन और वर्किंग प्लान अफसर और सर्किल प्रभारी, वन संरक्षक रीवा अनुराग कुमार की जमकर कत्ताल दी। इस मामले में मुख्य सचिव इस कदर नाराज थे कि उन्होंने सर्किल प्रभारी रीवा कुमार को निर्लंबित करने तक का कह दिया। बताया जाता है कि इस मौके पर वहां उपस्थित एसीएस अशोक वर्णवाल ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कुमार को सस्पेंड होने से बचाया।



तो हुई है, साथ ही उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है।

वन विभाग के इतिहास में पहली बार एक साल से पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर का पद खाली है। राज्य शासन ने पिछली जुलाई 25 में एक शिकायत के आधार पर 2010 बैच की वन्य प्राणी विशेषज्ञ आईएफएस अधिकारी अंजना सुचिता तिर्की को हटा दिया था। इसके बाद आज तक किसी भी आईएफएस अधिकारी की पूर्णकालिक फील्ड डायरेक्टर की पोस्टिंग यहां नहीं हुई। इसी प्रकार 11 जनवरी 2026 से संजय नेशनल पार्क में फील्ड डायरेक्टर का पद खाली है।

वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन को खुर्द-बुर्द करने के मामले में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वन बल प्रमुख शुभ रंजन सेन और वर्किंग प्लान अफसर और सर्किल प्रभारी, वन संरक्षक रीवा अनुराग कुमार की जमकर कत्ताल दी। इस मामले में मुख्य सचिव इस कदर नाराज थे कि उन्होंने सर्किल प्रभारी रीवा कुमार को निर्लंबित करने तक का कह दिया। बताया जाता है कि इस मौके पर वहां उपस्थित एसीएस अशोक वर्णवाल ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कुमार को सस्पेंड होने से बचाया।

हेल्थ सेक्टर में बढी प्रोफेशनल्स

डॉक्टरों को भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता है, क्योंकि मरीजों की जान बचाने और स्वस्थ करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाते तो आप हेल्थकेयर सेक्टर की दूसरे विंग के साथ जुड़कर अपनी यह मुराद पूरी कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर के तहत आने वाले कोर्सेज में नौकरियों के अवसर ही अवसर हैं। इसके तहत आने वाले कोर्सेज मुख्य रूप से रेडियोग्राफी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, जैसे कई फील्ड शामिल हैं। खास बात यह कि इसके तहत कई जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी चला जा रहे हैं। इन कोर्सेज को पढ़ने के लिए उम्मीदवार फुल टाइम क्लासेज का विकल्प चुन सकते हैं।

मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नोलॉजी



मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डॉक्टरों के निर्देश पर काम करते हैं, उपकरणों के रख-रखाव और कई तरह के काम इन्हीं के जिम्मे होता है। लैबोरेट्री में नमूनों की जांच और लैब में काम आने वाला घोल भी यही टेक्नीशियन बनाते हैं, इन्हें मेडिकल साइंस के साथ-साथ लैब सुरक्षा नियमों और जरूरतों के बारे में पूरा ज्ञान होता है। लैब टेक्नीशियन नमूनों की जांच का काम करते हैं, लेकिन ये इसके परिणामों के विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित नहीं होते नमूनों के परिणामों का विश्लेषण पैथोलॉजिस्ट या लैब टेक्नोलॉजिस्ट ही कर सकता है।

रेडियोलॉजी-एक्सरे टेक्नोलॉजी



एक्स रे लेता है जो रोगग्रस्त होता है ये एक्स रे उपचार में काफी सहायक होते हैं। अस्पताल, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, मिलिट्री सर्विस, शिक्षा संस्थानों, रिसर्च लैबोरेटरी के अलावा इनकी मांग सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में होती हैं। केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हेल्थ सेक्टर में विशेषज्ञ तथा ट्रेड रेडियोलॉजिस्ट की काफी आवश्यकता महसूस की जा रही है। अमेरिकन सोसायटी ऑफ रेडियोलॉजी की रिपोर्ट पर गौर करें तो सालाना 16 प्रतिशत की दर से इसमें बढ़ोतरी की संभावना है, जाहिर है ऐसे में रोजगार की संभावना भी बढ़ेंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट

आई है जिससे पता चलता है कि सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की कितनी डिमांड है।



डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करना जरूरी है। एक ऑर्थेलमिक असिस्टेंट का काम आंखों की डाइग्नोसिस के साथ-साथ ट्रीटमेंट व बचाव का प्रशिक्षण देना है, इसके अलावा क्लीनिकल डाटा इकटठा करना, पेशेंट के रिकार्ड को मंटेन करने का जिम्मा भी होता है। ऑर्थेलमिक के तहत कई तरह की आंखों से संबंधित क्लीनिकल फंक्शन किए जाते हैं। ऑर्थेलमिक असिस्टेंट आई डॉक्टर को पेशेंट की हिस्ट्री और कई तरह की तकनीकी जांच में मदद करता है।

नर्सिंग



हेल्थ सेक्टर के तहत आने वाला यह एक बेहद लोकप्रिय प्रोफेशन है और मेडिकल केयर का अहम हिस्सा भी हैं। जनरल बॉर्ड से लेकर ऑपरेशन थियेटर तक नर्सिंग स्टफ एक रोगी की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।इस कोर्स की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद आपके लिए जॉब के कई रास्ते खुल जाते हैं। दरअसल, इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज रोजगार की कोई कमी नहीं है। आप हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, क्लीनिक और हेल्थ डिपार्टमेंट, ओल्ड एज होम्स, मिलिट्री हेल्थ सर्विस, स्कूल्स, रेलवे, पब्लिक सेक्टर मेडिकल डिपार्टमेंट आदि में कार्य कर

सकते हैं।



ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन मेडिकल के क्षेत्र में ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन के रूप में उज्ज्वल करियर बनाया जा सकता है। अपरेशन थियेटर टेक्नीशियन का काम कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें ऑपरेशन टूल्स से लेकर ऑपरेशन थियेटर की हाइजीनिक सफाई तक का विशेष ध्यान रखना शामिल है। ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन धैर्यपूर्वक डॉक्टरों की मदद करता है, वह इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि ऑपरेशन थियेटर पूर्णरूप से बैक्टीरिया तथा वायरस से मुक्त हो। ऑपरेशन थियेटर की समय-समय पर तकनीकी रूप से सफाई करवाने का जिम्मा भी ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन का ही होता है।

योग्यता

हेल्थ सेक्टर के तहत आने वाले इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स डिग्री और पीएचडी जैसे कोर्सेज किए जा सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं डिग्री कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी/मैस विषयों में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बारहवीं पास होना चाहिए।

अवसर

डीपीएमआई की प्रिंसिपल के मुताबिक हेल्थ सेक्टर्स में आज कई लाख प्रोफेशनल्स की डिमांड है। निजी एवं सरकारी अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल कॉलेजों, इमेजिंग सेंटर, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसियों जैसे डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ रेडियोलॉजी व एर्टीमिक रिसर्च सेंटर में नौकरी के मौके उपलब्ध हैं, विदेशों में भी इन प्रोफेशनल्स की भारी डिमांड है।

वेतन

हेल्थ सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल्स की आज पूरी दुनिया में डिमांड है।अमेरिका, कनाडा, यूके, यूएई जैसे खाड़ी देशों में भी अवसर मौजूद हैं। इन प्रोफेशनल्स का वेतन उनकी कुशलता और अनुभव के अनुसार तय किया जाता है, शुरुआती वेतन 15 हजार रुपए से होता है। स्किल्स और अनुभव के साथ सैलरी में इजाफा होता चला जाता है। विदेश में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की सैलरी ज्यादा होता है।

प्रमुख संस्थान

- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली
- दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रीहैबिलिटेशन, मुंबई
- निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, लखनऊ

संभालकर बनाएं आर्ट रेस्टोरेशन में करियर



आर्ट रेस्टोरेशन , नाम सुनकर हो सकता है यह आपको थोड़ा नया लगे लेकिन क्या आपको हिट फिल्म लव आजकल में दीपिका पादुकोण का किरदार याद है ? जिसमें दीपिका ने आर्ट रेस्टोरेटर मीरा पंडित की भूमिका निभाई है। इस यादगार किरदार के साथ ही ऑन डिमांड करियर बन गया है आर्ट रेस्टोरेशन।

यह करियर प्रोफेशनल पेंटिंग का ही एक अलग रूप है, जिसमें पुरानी हवेलियों या किलों की खराब हो चुकी आर्ट को फिर से नया बनाया जाता है। प्राचीन कलाकृतियां, मूर्तियां, पेंटिंग्स आदि किसी भी देश की अमूल्य धरोहर समझी जाती हैं। कलाकृतियों के संरक्षण व रख-रखाव का यह कार्य आर्ट-रेस्टोरर द्वारा किया जाता है। योग्यता : आर्ट- रेस्टोरर बनने के लिए फाइन आर्ट तथा रसायन विज्ञान में स्नातक होना अनिवार्य है। इस क्षेत्र में दो साल का मास्टर डिग्री कोर्स कराया जाता है। जिसके तहत आपको पेंटिंग रेस्टोरेशन, मेटल वर्क, टेक्सटाइल, पेपर वर्क और मैयूस्क्रिप्ट आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। योग्यता कंजर्वेशन में मास्टर डिग्री कोर्स करने के लिए आपके पास कंि म स्ी , जि यो ल ी , फिजिक्स, बॉटनी, जूलोजी, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर , आर्कियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी में से किसी एक विषय में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इससे संबंधित कोर्स करने के लिए फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ संस्थानों में स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है।

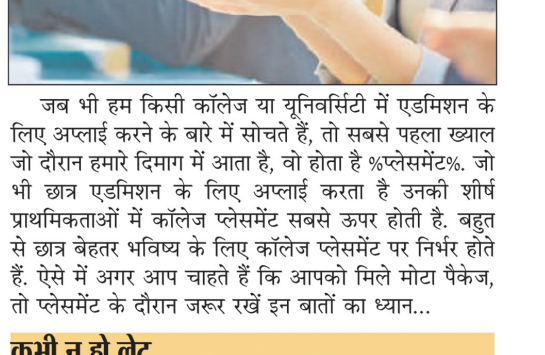
संभानाएं: ऐतिहासिक इमारतों को संजोकर रखने में पुरातत्व विभाग के रेस्टोरर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रेस्टोरेशन का काम सिर्फ सरकारी विभागों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने एक उद्योग का रूप ले लिया है। जॉब की संभावनाएं इस कोर्स को करने के बाद आपको आर्ट गैलरी, म्यूजियम सहित कई जगहों पर काम मिल जाता है। शुरु में आपको अनुभव हासिल करने के लिए किसी अच्छे आर्ट रेस्टोरर के साथ काम करना पड़ सकता है। कुछ साल का अनुभव होने के बाद आप अपना प्राइवेट वर्क भी शुरू कर सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी में भी आपको मौका मिलता है। कोर्स को करने के बाद आपको सरकारी नौकरी भी मिलती है।

प्रमुख संस्थान: नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली प्रवेश: पेंटिंग से संबंधित कोर्स में एडमिशन लेने के लिए किसी भी स्टीम में ग्रेजुएट होना आवश्यक है। शॉर्ट- टर्म कोर्स के लिए कम से कम बारहवीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखने वालों को इसे सीखने में आसानी होती है। इसके अलावा आपमें क्रिएटिविटी और संगीत की समझ होने की भी जरूरत होती है। संभावनाएं: एलबुलई कोर्स करने और इसमें कुशलता हासिल करने के बाद विभिन्न चैनल्स न्यूज एवं एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन हाउस और फिल्म कंपनियों में आसानी से काम मिल जाता है। कोर्स करने के बाद प्रोडक्शन हाउस या टेलीविजन चैनल में आकर्षक वेतन मिलता है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान

- भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली
- मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली
- कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
- डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे
- सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पुणे
- दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हैरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट, दिल्ली
- नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, लखनऊ

कॉलेज प्लेसमेंट में पाना चाहते हैं मोटी सैलरी, तो करें ये काम



जब भी हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला खयाल जो दौरान हमारे दिमाग में आता है, वो होता है %प्लेसमेंट% जो भी छात्र एडमिशन के लिए अप्लाई करता है उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में कॉलेज प्लेसमेंट सबसे ऊपर होती है. बहुत से छात्र बेहतर भविष्य के लिए कॉलेज प्लेसमेंट पर निर्भर होते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले मोटा पैकेज, तो प्लेसमेंट के दौरान जरूर रखें इन बातों का ध्यान...

कभी न हो लेट

समय पर न पहुंचने वालों का हर एक जगह खराब इम्प्रेशन ही पड़ता है. फिर चाहे बात कॉलेज प्लेसमेंट की ही क्यों न हो. इंटरव्यू राउंड में देरी से पहुंचने वालों के सेलेक्ट होने के चांसेज न के बराबर रह जाते हैं, क्योंकि एक पचआर को इंटरव्यू के दौरान देरी से पहुंचने वाले उम्मीदवार बिलकुल रास नहीं आते हैं.

बेसिक को न करें नजरअंदाज

बहुत से उम्मीदवार इंजीनियरिंग के शुरुआती सालों में पढ़ाए गए बेसिक्स को नजरअंदाज कर देते हैं और प्लेसमेंट से पहले इन्हें दोबारा रिवाइज न करने की गलती कर बैठते हैं. जबकि प्लेसमेंट के दौरान अक्सर नियोका बेसिक से जुड़े सवाल पूछते हैं. इसलिए जब भी आप कॉलेज प्लेसमेंट के लिए जाए तो एक बार अपने बेसिक्स का रीविजन कर के जाएं.

अंग्रेजी की है डिमांड

आपको चाहे ये बात अच्छी लगे या न लगे पर अच्छी अंग्रेजी लिखने और बोलने वाले लोगों की भारतीय जॉब मार्केट में काफी डिमांड है. हालांकि इस बात को जानते हुए भी बहुत से लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान नहीं देते हैं. अगर आपको लगता है कि आप अंग्रेजी बोलने और लिखने में थोड़े कमजोर हैं तो प्लेसमेंट पर जाने से पहले इस पर जरूर थोड़ा काम कर के जाएं.

फीडबैक लेना न भूलें

एक बार इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद आपको नियोका से अपना फीडबैक भी ले लेना चाहिए, भले ही आपका चयन न हुआ हो. ऐसा करने का फायदा आपको भविष्य में मिलेगा, क्योंकि इससे आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलता है. इसकी मदद से आप प्लेसमेंट के दौरान दूसरी कंपनियों के सामने खुद को बेहतर ढंग से पेश कर पाएंगे.



आज कल कोई भी ईसान ऐसा नहीं है जो इंटरनेट का प्रयोग ना करता हो। लेकिन आप बिना किसी इंटरनेट के भी घर बैठे अपनी स्किल की बढ़ौतल अच्छी-खासी इनकम की जा सकती। वह तरीका है- हैंडराइटिंग जॉब का। चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों के लोग हैंडरिटिन नोट्स के जरिए अच्छी कमाई कर रहे हैं। बड़ी बात कि इसके लिए कंप्यूटर और इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। इस जॉब से आप कुछ घंटे लगाकर हर महीने औसतन 15-20 हजार रुपए तक इनकम कर सकते हैं।

बुक पब्लिकेशन

बुक पब्लिकेशन के क्षेत्र में हैंडराइटिंग जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत है। इन्फार्मेशन के लिए आज विकिपीडिया और गूगल सर्च जैसी वेबसाइट्स हैं। लेकिन, आज भी कई स्टूडेंट इन्फार्मेशन के लिए किताबों पर निर्भर हैं। हैंडराइटिंग जॉब का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स के लिए विक्क शॉर्ट नोट बुक पब्लिशिंग, विक्क क्वेश्चन- आंसर बयएसरुक और विक्क सजेसन बुक के लिए है।

इनकम

हैंडराइटिंग जॉब से सामान्यत एक रुपए प्रति लाइन की इनकम हो सकती है। विक्क सजेसन बुक और क्वेश्चन-एन्सर के हर जवाब की एक लाइन के लिए एक रुपया तक मिलता है। इस तरह, आप हर रोज अपनी हैंडराइटिंग स्किल से 500 रुपए तक की इनकम कर सकते हैं। महीने की इनकम 15 हजार रुपए या इससे ज्यादा हो सकती है। हैंडराइटिंग जॉब पाने के लिए न्यूजपेपर्स की वलासीफाइड ऐड, ओएलएक्स या विक्क पर सर्व कर कर सकते हैं। आप फ़िक्र पर हैंडराइटिंग जॉब की जरूरत के लिए फ्री ऐड पोस्ट कर सकते हैं। विक्क टीम आपको खुद सजेस्ट करेगी।

शुरु कर सकते हैं बिजनेस

हैंडराइटिंग जॉब से अधिक इनकम के लिए आप खुद एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे आपको काम करने की फ्रीडम के साथ-साथ ज्यादा इनकम भी होगी। हैंडराइटिंग जॉब बिजनेस के लिए रिववायरमेंट बुक पब्लिशर कंट्रीब्यूटर, डाटा कन्जर्नशन, होम बेस ट्यूटर से सबसे ज्यादा मिलती है। हैंडराइटिंग बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको होम बेस ट्यूटर से संपर्क करना होगा। इसके लिए आपको पास नई बुक पब्लिश करने का आईडिया होना चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अछा यह है कि इसकी शुरुआत स्मॉल लेवल पर की जाए। पहले साल में आप 3 बुक ही पब्लिश कराने का प्लान बनाएं। इसमें भी बेहतर यह होगा कि प्रत्येक वर्ल्स की सजेक्ट के अनुसार शॉर्ट क्वेश्चन-एन्सर बुक पब्लिश कराएं। इस बिजनेस के लिए आप कुछ लोगों को हायर कर सकते हैं। उनसे वय निर्देशों के अनुसार क्वेश्चन-एन्सर बुक के लिए हैंडराइटिंग करा सकते हैं।

करियर का अच्छा मौका है फैशन



रंगो और कपड़ों के संयोजन से एक ऐसी पोशाक बनाना जिसको देखकर लोगो के मुह से वाओ शब्द निकल जाये यही असली मायने में फैशन कहलाता है. आज के युग को फैशन का युग कहा जाता है. दुनिया का चक्काचौद में हर कोई फैशन के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। फैशन डिज़ाज़निंग को आम तौर पर करियर का एक आप्शन भर माना जाता है. जबकि ऐसा नहीं है, दरअसल यह एक ऐसी कला है जो ड्रेस और एक्सेसरीज़ की मदद से किसी इन्सान की लाइफ टाइटल को सामने लाती है

क्या है फैशन डिज़ाज़निंग?

मॉडर्न फैशन के अंतर्गत दो विभाग हैं. पहला वर्ग है पोशाकों को डिज़ाइन करना और दूसरा रेडी-टू-वियर अर्थात तैयार पोशाकें। इन दोनों वर्गों में फैशन डिज़ाज़निंग का इस्तेमाल प्रथम वर्ग में किया जाता है। वर्तमान समय में फैशन शो इसी के ख़ते चल रहे हैं। इन शो के ज़रिए ही फैशन डिज़ाज़र्स की सृजनात्मकता और रचनात्मकता

मौसम के साथ बदलता है फैशन का भी

मिजाज यह भी जरूरी है की इसे पूरी विधि के साथ संपूर्ण किया जाए। प्लान तैयार करके, ब्लू प्रिंट्स ड्रा करने के बाद ही फाइनल आउटकम प्राप्त होगा। डिज़ाइन की सफलता स्वाभाविक रूप से उसकी फिनिशिंग फैशन डिज़ाज़निंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि फैशन किसी ना किसी थीम पर निर्भर करता है. जैसे- मौसम, लोगो की पसंद विशेष आदि, अगर आपने गौर किया हो तो फैशन प्रमुखत- मौसम के अनुसार होता है. उदाहरण के लिए सर्दी के मौसम में आपको उसी के अनुरूप रंग और फैब्रिक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ऊनी कपड़े, पोलो नेक, नीले और ब्राउन देखने को मिलेंगे. इसके विपरीत गर्मियों में आपको केजुअल, कौटन और स्फ़े़ड रंग मिलेंगे।



क्या है इन और क्या है आउट

फैशन कभी भी स्थायी नहीं होता है,समय के स।थ इसमे परिवर्तन होते रहते हैं। वर्तमान ने स्पोर्टी का फैशन गया और हॉल्टर नेवस चल रहे हैं। स्कर्ट चल में हैं और पैंटसूट्स का दौर जा चुका है। इसीलिए परिवर्तन की गति को देखते हुए, इस फील्ड में आने व।ले हर ईसान को चौकन्ना रहना होगा। और इस बात के लिए कि क्या पहना जाना चाहिए और क्या नहीं? फैशन का प्रमुख केंद्र सैलिब्रिटीज, सोशलाइटर्स, मॉडल्स आदि रहे हैं।

ग्लैमर कम नहीं

कुल मिलाकर फैशन डिज़ाइनिंग बहुत ही चुनौती भरा और ग्लैमर से भरपूर भरा व्यवसाय है, जिसमे राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होते हैं. जैसे: आईएमजी फैशन वीक, लक्मे फैशन वीक आदि। बहुत से फैशन डिज़ाइनिंग इन्स्टिट्यूट जैसे: नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद, नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नलॉजी, स।फिया पॉलि टेक्निक आदि।

शिक्षा में भी सांप्रदायिकता देखती है भाजपा: अखिलेश

लखनऊ।



रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद और गहरा गया है. 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर शिक्षा को सांप्रदायिक नजरिए से देखने का आरोप लगाया है. वहीं पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी के गेट पर बोर्ड लगाकर सड़क को आम जनता का रास्ता बताया है. मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई के साथ राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन गया है. उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं. रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को बिना स्वीकृत नक्शे के अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किए जाने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत भी गरमा गई है. अखिलेश ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।

शरद और सुनेत्रा गुट का होने वाला है विलय?

मुंबई।



महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ समय से एनसीपी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) के बीच विलय की अटकलें लगाई जा रही हैं, अब इस पर महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने गुरवार को कहा कि शरद पवार गुट के साथ फिलहाल विलय की लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपनी मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि दो दिन पहले हुई यह बैठक केवल उनके लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर थी. उन्होंने बताया कि एक दिन पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन भाजपा की कौर कमेटी की बैठक के कारण मुलाकात नहीं हो सकी.तटकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ मेरी मुलाकात सिर्फ मेरे लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर थी। हमें सरकार के साथ वित्त विभाग से जुड़े मामलों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करनी है।

उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बगावत!

नईदिल्ली।



नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद आगा रहुल्लाह मेहदी ने पार्टी के उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बागावत कर मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने सीएम उमर को बीजेपी एजेंट होने का गंभीर आरोप लगाया है. आगा रहुल्लाह मेहदी ने बुधवार को अनंतनाग में दिए अपने भाषण कहा, हमारे आज के शासक ने चुनाव अभियान के दौरान वोटों के लिए अपनी टोपी तक उतार दी थी. उन्होंने जनता से जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाली का बड़ा वादा किया था, लेकिन आज वो पूरी तरह से खामोश हैं और केवल राज्य के दर्जे के लिए लड़ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आज का शासक जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक अधिकार छीनने के लिए बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला पा रहा है.उमर अब्दुल्ला के खिलाफ हमला जारी रखते हुए एनसी सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए राज्य का दर्जा चाहते हैं।

ममता को एक और झटका, सांसद राज्यसभा से इस्तीफा

बंगाल।



तृणमूल कांग्रेस की सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है. कोयल मल्लिक टॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं. कोयल मल्लिक का इस्तीफा पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के लिए एक और झटका माना जा रहा है. बुधवार को पार्टी नेता मदन मित्रा ने भी ममता का साथी छोड़ दिया था और ऋतब्रत खेमे में चले गए थे. आज अब सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है.कोयल मल्लिक का असली नाम रश्मिणी मल्लिक है.वे एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री हैं. वे मुख्य रूप से टॉलीवुड की टॉली-क्रोन के नाम से जानी जाती हैं. राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को लिखे एक पत्र में कोयल मल्लिक ने कहा है कि वे अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं. कृपया इसे स्वीकार किया जाए, उन्होंने राज्यसभा के सभी अधिकारियों और सदस्यों को धन्यवाद दिया है. कोयल मल्लिक ने 6 अप्रैल को राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ली थी।

कोरोना की वापसी की आशंका- 4 मोर्तें और 12 नए केस से हड़कंप

नई दिल्ली।



देश में कोविड-19 के कुछ नए मामलों और मौतों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है, जिससे बीमारी की वापसी का खतरा मंडराने लगा है। आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के बीच 12 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए, जिनमें से चार मरीजों की पहले से मौजूद गंभीर बीमारियों और कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के कारण मौत हो गई। इन मौतों का अनुयात लगभग 30 प्रतिशत रहा, जिसने लोगों को विशेष रूप से भयभीत कर दिया है। मरने वाले मरीजों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज और किडनी संबंधी गंभीर समस्याएं थीं। शेष संक्रमितों में से तीन होम आइसोलेशन में हैं, दो अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, जबकि तीन ठीक होकर घर जा चुके हैं। जुलाई के पहले पखवाड़े में देशभर में कुल 339 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जो सतर्कता की आवश्यकता को दर्शाते हैं। हालांकि, संक्रामक रोग विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल देश में कोरोना की कोई नई लहर नहीं है और न ही कोई खतरनाक वैरिएंट सामने आया है। आंध्र प्रदेश के मामले स्थानीय क्लस्टर प्रतीत होते हैं।

पीएम मोदी ने देश को दी हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात

प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद में दिखाई हरी झंडी, जींद और सोनीपत के बीच चलेगी यह स्वदेशी ट्रेन

जींद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन-पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जहाँ हाइड्रोजन-पावर्ड ट्रेनें चल रही हैं। भारत में डिजाइन और तैयार की गई यह ट्रेन साफ़-सुथरे रेल ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन-पावर्ड पैसेंजर ट्रेनों में से एक है। इसमें 10 कोच हैं, लगभग 2,600 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और 3,200 हॉर्सपावर का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है। दुनिया भर में अभी चल रही ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनों में सिर्फ़ दो से चार कोच होते हैं और उनका इस्तेमाल मुख्य रूप से छोटे रीजनल रूट पर किया जाता है।

हाइड्रोजन से चलने वाली यह ट्रेन शुरुआत में हरियाणा में नॉर्दन रेलवे के 89 किलोमीटर लंबे जींद-सोनीपत सेक्शन पर चलेगी। इस लॉन्च के साथ, भारत हाइड्रोजन से चलने वाले रेल ट्रांसपोर्ट की दिशा में काम करने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है। पारंपरिक डीजल लोकोमोटिव के विपरीत, हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन प्यूल सेल का इस्तेमाल करके खुद अपनी बिजली बनाती है।

भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। देश के नेतृत्व की वजह से हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी विकसित करने में हमने एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी मौजूद है।

इस सिस्टम का मुख्य हिस्सा 1,200-किलोवाट का प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन प्यूल सेल (PEMFC) है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कैमिकल रिएक्शन से बिजली बनाता है। इससे निकलने वाली एकमात्र चीजें पानी की भाप और गर्मी हैं, जो इसे आज उपलब्ध रेल प्रोपल्शन के सबसे साफ़ तरीकों



में से एक बनाती हैं। ट्रेन अपने दो हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कारों के अंदर लगे हाई-प्रेशर सिलेंडरों में कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस ले जाती है। यह हाइड्रोजन एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन प्यूल सेल (PEMFC) में भेजा जाता है, जो एक बैटरी की तरह काम करता है; जब तक हाइड्रोजन की सप्लाई होती रहती है, तब तक इसे कभी रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

प्यूल सेल के अंदर, आमतौर पर प्लेटिनम से बने कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन के अणुओं को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ा जाता है। प्रोटॉन एक खास पॉलीमर झिल्ली से गुज़रते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को एक बाहरी इलेक्ट्रिक सर्किट से होकर गुज़रने के लिए मजबूर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की इस गति से विद्युत उत्पन्न होती है, जो ट्रेन के ट्रैक्शन मोटर्स को शक्ति प्रदान करती है। साथ ही, आसपास की हवा से ऑक्सीजन ईंधन सेल में प्रवेश करती है और हाइड्रोजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ जाती है। इस विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के एकमात्र उप-उत्पाद जल वाष्प और ऊष्मा हैं। इसमें कोई दहन नहीं होता, कोई धुआँ नहीं निकलता और उपयोग स्थल पर लगभग कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता।

14700 करोड़ रुपये की विकास

परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा के

जींद में एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में आयोजित किया गया। मुख्य प्रोजेक्ट्स में 12,470 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाले नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 9,680 करोड़ रुपये की लागत से बने 157.92 किलोमीटर लंबे, चार-लेन वाले और पूरी तरह से एक्सप्रेस-कंट्रोल दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (पैकेज 1 से 5) को देश को समर्पित किया।

667 किलोमीटर लंबे दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा रहे इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय लगभग 14 घंटे से घटकर छह घंटे और दिल्ली और अमृतसर के बीच लगभग आठ घंटे से घटकर चार घंटे होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट का मकसद एनएच-44 (जीटी रोड) पर भीड़ कम करना, श्री माता वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की आवाजाही को बेहतर बनाना और कॉरिडोर के साथ-साथ इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है।

इस दौरान मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जींद को इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम-राम। आज इस पवित्र धरती पर आकर हम गदगद हो गया है। यो कोई साधारण धरती नहीं से,

यो धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो जींद आना पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है। कई दशक पहले मैं संगठन के काम से पहली बार जींद आया, फिर आप लोगों ने मुझे जो अपनत्व दिया, प्रेम दिया, वो मैं आज आज तक भुला नहीं हूँ। इतने वर्षों में जींद के घी और जींद के घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जींद के तेवर बदल गए हैं। आज जींद भाजपा-एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में पूरा हरियाणा ही विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की भाजपा सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है। आज जींद और हरियाणा का नाम इतिहास पन्नों में दर्ज हो हो गया है। आज यहां देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। उन्होंने कहा कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा, तो जींद के , सोनीपत का और हरियाणा का नाम आएगा ही आएगा। उन्होंने कहा कि आज 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट्स भी हरियाणा को मिले हैं। इसमें रेलवे के, हाईवे के अनेक नए प्रोजेक्ट हैं, हमारी विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं और 2 मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित हैं।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज जींद वालों से कुछ मांगने आया हूँ। क्या इस सफाई और स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी है? अगर जींद और हरियाणा के लोग तय कर लें कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे। तो जींद और हरियाणा अभी गंदा हो ही नहीं पाएगा। स्वच्छता को हमारा स्वभाव बनाएंगे। स्वच्छता को हमारा संस्कार बनाएंगे। हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से थी। 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21 वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है।

एफसीएनआर योजना से भारत आ सकते हैं 70-80 अरब डॉलर

सिंगापुर।

अनिवासी भारतीय मौजूदा एफसीएनआर पहल के तहत भारत में 70-80 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा ला सकते हैं। इसके तहत बैंक सीमित अवधि के लिए एफसीएनआर जमा पर अधिक ब्याज दर की पेशकश कर रहे हैं। सिंगापुर के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने शुक्रवार को यह बात कही। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की सिंगापुर शाखा द्वारा बुधवार को आईसीएआई की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति और उसकी 25 विदेशी शाखाओं के सहयोग से आयोजित वैश्विक वेबिनार में भी इस पर चर्चा की गई। विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) योजना के तहत एनआरआई और भारतीय मूल के व्यक्ति भारतीय बैंकों में प्रमुख विदेशी मुद्राओं में अपनी विदेश में अर्जित आय को सुरक्षित रूप से जमा कर उस पर प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं।

पेप्सिको को दूसरी छमाही में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

नई दिल्ली।

खाद्य एवं पेय पदार्थ क्षेत्र की प्रमुख कंपनी पेप्सिको के भारत और दक्षिण एशिया के सीईओ जागृत कोटेचा ने कहा कि कंपनी को 2026 की दूसरी छमाही में अपने कारोबार के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि महंगाई के दबाव के बावजूद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मांग मजबूत बनी हुई है। कोटेचा ने उद्योग निकाय फिक्की द्वारा आयोजित फूडवर्ल्ड इंडिया के इतर कहर, हमारे द्वारा और पेय दोनों व्यवसायों के लिए पहली छमाही अच्छी रही है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि व्यापक रही, जो दोनों पोर्टफोलियो, सभी क्षेत्रों और शहरी व ग्रामीण बाजारों में देखी गई। कोटेचा ने कहा कि कंपनी दूसरी छमाही के प्रदर्शन को लेकर सतर्क रूप से आशान्वित है। हालांकि, पेप्सिको अल नीनो जैसी मौसम संबंधी चुनौतियों के साथ-साथ वैश्विक और घरेलू स्तर की अन्य अनिश्चितताओं पर नजर बनाए हुए है, जो उपभोक्ता मांग को प्रभावित कर सकती हैं।

चीन की रेयर अर्थ नीति से बढ़ी टेंशन

नईदिल्ली।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ‘ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स आउटलुक 2026’ की रिपोर्ट के अनुसार, यदि चीन रेयर अर्थ के निर्यात प्रतिबंधों को पूरी तरह लागू कर देता है, तो चीन से बाहर पूरी दुनिया में हर साल लगभग 6.5 लाख करोड़ डॉलर का औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसका असर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, रक्षा, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर पड़ने की आशंका है। रेयर अर्थ 17 महत्वपूर्ण खनिजों का समूह है, जिनका उपयोग स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, विंड टरबाइन, लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट और अन्य हाई-टेक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। इनकी लागत किसी उत्पाद में कम होती है लेकिन इनकी अनुपलब्धता पूरी उत्पादन प्रक्रिया को रोक सकती है।

स्टेल प्रमुख समाचार

विश्व कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम घोषित

नई दिल्ली।



हॉकी विश्व कप 2026 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कप्तान सलीमा टेटे को सौंपी गई है। अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के संतुलित मिश्रण वाली यह टीम आगस्त में नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले विश्व कप में चुनौती पेश करगी। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच स्योर्ड मारिजने ने चुनी गई टीम को संतुलित बताया है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त के बीच खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी नीदरलैंड और बेल्जियम संयुक्त रूप से करेंगे। बंगलूरू के राष्ट्रीय शिविर में तैयारी कर रही इस टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभाओं को भी जगह मिली है। इन खिलाड़ियों ने हालिया अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में प्रभावित किया है। पिछले महीने न्यूजीलैंड में खेले गए एफआईएच नेशंस कप में भारत ने बिना कोई मैच गंवाए खिताब अपने नाम किया था। भारतीय टीम को पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है। टीम अपने सभी ग्रुप मुकाबले नीदरलैंड के एमस्टेलवीन स्थित वागोनर हॉकी स्टेडियम में खेलेगी। भारत अपने अभियान की शुरुआत 16 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगा। इसके बाद 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका और 20 अगस्त को इंग्लैंड से भिड़ेगा।

एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2026

के लिए भारत की 20 सदस्यीय टीम

गोलकीपर: सविता, चिंदी देवी खारीबम।
डिफेंडर: इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथंतलुंगी, ज्योति, शिल्पी डबास।
मिडफील्डर: निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलित्ता टोप्पो, सलीमा टेटे (कप्तान), नेहा, दीपिका सोंरेंग।
फॉरवर्ड: लालरेमियामी, रलुजा दादासो पिसल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर, ब्यूटी डुंगडुंग।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

कतिताल मांडोत

देश में महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जून महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38 प्रतिशत पर पहुंच गई है। पिछले 17 महीनों में यह पहला अवसर है जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 4 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर पहुंची है। इससे पहले मई में खुदरा महंगाई 3.95 प्रतिशत दर्ज की गई थी। महंगाई में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगावत हुई वृद्धि का परिणाम मानी जा रही है। इसके साथ ही परिवहन लागत बढ़ने से रोजमर्रा की ज़रूरत का लगभग हर सामान महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर दिखाई देने लगा है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में खाद्य

महंगाई बढ़कर 5.32 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि मई में यह 4.78 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 5.45 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5.09 प्रतिशत दर्ज की गई। यह स्पष्ट संकेत है कि गांव और शहर दोनों ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। फल, सब्जियां, दालें, खाद्य तेल, दूध तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने रसोई का खर्च काफी बढ़ा दिया है। मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए घर का बजट संभालना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गया है।

महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हुई वृद्धि भी रही है। ईंधन महंगा होने से माल दुलाई की लागत बढ़ गई है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने का असर केवल परिवहन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव हर उस वस्तु पर पड़ता है जिसे एक स्थान से



दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। किराना, फल-सब्जियां, दवाइयां, कपड़े, निर्माण सामग्री और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी परिवहन खर्च बढ़ने के कारण ऊपर चली जाती हैं। जून महीने में माल दुलाई से जुड़ी सेवाओं की महंगाई दर बढ़कर लगभग 7.70 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो यह बताती है कि परिवहन लागत अब महंगाई का बड़ा कारण बन चुकी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी

ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव भारत जैसे आयात पर निर्भर देश पर पड़ता है। भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में वैश्विक परिस्थितियां बिगड़ने पर घरेलू बाजार में भी पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का असर अब सीधे आम नागरिक की जेब पर महसूस किया जा रहा है।

महंगाई बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए नया आधार वर्ष और नई उपभोक्ता टोकरी लागू होने के बाद यह महंगाई का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। नई उपभोक्ता टोकरी में लोगों की वर्तमान जीवनशैली और खर्च के

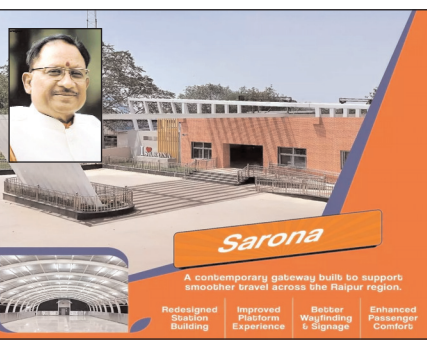
पैटर्न को अधिक वास्तविक रूप से शामिल किया गया है। इससे महंगाई का आकलन पहले की तुलना में अधिक सटीक माना जा रहा है। हालांकि इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि लोगों के दैनिक खर्च में वास्तविक बढ़ोतरी पहले के अनुमान से अधिक है।

महंगाई का सबसे अधिक असर निश्चित आय वाले परिवारों पर पड़ता है। जिन लोगों की आय सीमित है या जिनकी आय में नियमित वृद्धि नहीं होती, उनके लिए बढ़ती कीमतों के बीच खर्चों का संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वेतनभोगी कर्मचारियों, छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर और पेंशनभोगी सभी इस स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं पर अधिक खर्च होने के कारण लोग अन्य ज़रूरतों पर खर्च कम करने को मजबूर हो रहे हैं। इससे उपभोक्ता मांग पर भी असर पड़ सकता है, जो आवश्यकवस्था की गति को प्रभावित करता है।

रेल विकास को नई रफ्तार, जनसुविधाओं का सशक्त विस्तार: मुख्यमंत्री साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना विकास को नई गति मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के चांपा, बालोद और सरोना रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के रेल विकास और जनसुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए गए ये रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उनकी यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित, सरल और आरामदायक बनेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन केवल आवागमन के केंद्र नहीं होते, बल्कि वे किसी भी क्षेत्र के

आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।सीएम साय ने कहा कि चांपा, बालोद और सरोना रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर यात्री सुविधाओं के साथ इन क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे सुविधाओं के विस्तार से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में रेलवे क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से पुराने रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कई रेलवे स्टेशनों को भी विकसित किया जा रहा है, जिससे



प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है।उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकारी प्रयासों से छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। राज्य में नई रेल परियोजनाओं, बेहतर यात्री सुविधाओं और आधुनिक तकनीक के उपयोग से रेलवे व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इससे प्रदेश के लोगों को आवागमन में

सुविधा मिलने के साथ उद्योग और व्यापार को भी लाभ मिलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इनमें बेहतर प्रतीक्षालय, साफ-सफाई व्यवस्था, सुगम प्रवेश और निकास, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, यात्री सुविधाओं का विस्तार और स्टेशन परिसर का आकर्षक विकास शामिल है। इन सुविधाओं का उद्देश्य यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करना है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस जनहितकारी पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों

से छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। रेलवे विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी क्षेत्र के विकास में मजबूत परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बेहतर रेल नेटवर्क से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलती है, बल्कि उद्योग, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को भी मजबूती मिलती है। चांपा, बालोद और सरोना रेलवे स्टेशनों का विकास भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण का कार्य लगातार जारी रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के अधिक से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाए, ताकि यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिले।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र दार्जिलिंग में पाँच दिवसीय बेसिक कमिश्नर कोर्स सम्पन्न



रायपुर। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, राष्ट्रीय मुख्यालय के तत्वावधान में 10 से 14 जुलाई 2026 तक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, कुर्सियांग में आयोजित पाँच दिवसीय बेसिक कमिश्नर कोर्स सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में छत्तीसगढ़ से राज्य मुख्य आयुक्त श्री इंंदरजीत सिंह खालसा सहित जिला मुख्य आयुक्त, सहायक जिला मुख्य आयुक्त एवं संगठन के अन्य पदाधिकारी कुल 41 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण का उद्देश्य कमिश्नरों के नेतृत्व कौशल, संगठनात्मक क्षमता, प्रशिक्षण प्रबंधन तथा स्काउट-गाइड गतिविधियों के प्रभावी संचालन को मजबूत करना था। प्रशिक्षण के दौरान नेतृत्व, अनुशासन, टीम भावना, निर्णय

क्षमता और व्यावहारिक गतिविधियों पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों को स्काउटिंग के सिद्धांत, संगठन संचालन, कार्यक्रम नियोजन, संचार कौशल, समस्या समाधान, टीम वर्क और सेवा भावना से जुड़े विषयों का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक सत्र ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा, जिससे प्रतिभागियों के व्यक्तित्व और संगठनात्मक दक्षता में सकारात्मक वृद्धि हुई। राज्य मुख्य आयुक्त इंंदरजीत सिंह खालसा ने कहा कि यह प्रशिक्षण उनके लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक रहा। इससे स्काउटिंग के प्रति समझ गतिविधियों के प्रभावी संचालन को, आत्मविश्वास और संगठनात्मक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

निर्माण गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा करने पर जोर: अनुराग सिंह

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध क्रियान्वयन और ठेकेदारों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से मंडल के अध्यक्ष अनुराग मीसंह देव एवं आयुक्त अरुणेश कुमार शरण की अध्यक्षता में निर्माण ठेकेदारों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 50 से अधिक निर्माण ठेकेदारों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों से मंडल द्वारा सभी निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा कर गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में मंडल के कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए आवास निर्माण के साथ-साथ



नगर विकास, रि-डेवलपमेंट, सड़क, पुन-पुलिया सहित अधोसंरचना विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी मंडल को सौंपी है। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों की भागीदारी इन योजनाओं की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। मंडल इन-हाउस, पीपीपी मॉडल तथा बीओटी के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का प्रभावी संचालन कर रहा है और ठेकेदार मंडल की विकास यात्रा के अभिन्न सहयोगी हैं।अध्यक्ष सिंह देव ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि हितग्राहियों के लिए बनाए जाने

वाले प्रत्येक घर का निर्माण उसी गुणवत्ता और संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए, जैसी गुणवत्ता कोई व्यक्ति अपने स्वयं के घर के निर्माण में सुनिश्चित करता है। बैठक में आयुक्त अरुणेश कुमार शरण ने कहा कि समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण विषयों— निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समय-सीमा में कार्य पूर्ण करना तथा ठेकेदारों के देयकों का समयबद्ध भुगतान-पर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करना है। उन्होंने कहा कि सभी अभियंताओं एवं ठेकेदारों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि आर्बिट्रल कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तथा तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं। कार्यस्थलों पर आने वाली वास्तविक समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर मुख्यालय से भी तत्काल मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल की सुनवाई 27 से

रायपुर। छत्तीसगढ़ के करदाता, विभागीय अधिकारी, अधिकृत प्रतिनिधि और वकील के लिए एक बड़ी खबर है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल की रायपुर बेंच 27 जुलाई से मामलों की सुनवाई शुरू करने जा रही है। जानकारी के अनुसार, ट्रिब्यूनल की सुनवाई अभी इसके अस्थायी परिसर में शुरू होगी, जो कि नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, वार्पिण्जिक कर- तस्झ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में स्थित है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, रायपुर बेंच में सभी श्रेणियों के मामलों को सोमवार से शुक्रवार तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।बेंच के सामने रोजाना पेश होने वाले मामलों की कार्य सूची जीएसटीएटी के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर कांज लिस्ट टैब के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।ट्रिब्यूनल प्रशासन ने सभी हितधारकों, वकीलों और करदाताओं से अपील की है कि वे अपने मामलों की ताजा स्थिति और तारीखों की जानकारी के लिए नियमित रूप से पोर्टल को चेक करते रहें।

नाबालिक और युवाओं में महामारी का रूप ले चुका है नशाखोरी': बैज

रायपुर। नशे के अवैध कारोबार के लिये सरकार जिम्मेदार है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब होकर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे सुखे नशे के अवैध कारोबार को भाजपा की डबल इंजन सरकार अकर्मण्यता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बिना सत्ता के संरक्षण के अवैध नशे का स्प्लाई नेटवर्क पाकिस्तान से पंजाब होकर छत्तीसगढ़ के गांव, गली मोहल्ले तक खुलेआम बिक रहे हैं, ऑनलाइन और व्हाट्सएप ग्रुप बनकर ड्रग पैडलर बेखौफ़ बेच रहे हैं, यह केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की विफलता है। पुलिस का डर अपराधियों में खत्म हो गया है, सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। छोटी मछलियों पर दिखावे की कार्यवाही करके सरकार असल मगरमच्छों को संरक्षण दे रही है, वर्तमान स्थिति में 80 लाख का हेरोइन जस होना तो बहुत ही मामूली है, नशे



का असल अवैध कारोबार हजारों करोड़ का है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की बिना सत्ता के संरक्षण के अवैध नशाखोरी महामारी का रूप ले चुका है, कमीशनरी प्रणाली लागू होने के बाद भी क्राइम बढ़ रहा है। न ही अवैध नशे पर लगाम लग पा रहा है। युवा और नाबालिक बुरी तरह से सुख नशे के चपेट में आ चुके हैं, बड़े शहरों के आउटर संचालित कैफे, फार्महाउस और बार में अवैध नशे का जमकर कारोबार हो रहा है। गंजा, अफीम, चरस, कोकीन, हेरोइन, एम डी एम ए, स्मैक, ब्राउन शुगर से लेकर कफ सिरप, नाइट्रोटेन, अल्ट्राजोलम, चंदागोली खुलेआम बिक रहा है। सरकार के दावे पूरी तरह से फेल हो

चुका है, अब तो छत्तीसगढ़ में ड्रग पैडलरों का पाकिस्तानी आईएसआईएस कनेक्शन सामने आ रहा है, सरकार का इंटेलीजेंस पूरी तरह से सरेंडर की मुद्रा में दिख रहा है। राजधानी के हाइपर क्लब, आईपी क्लब गोलीकांड, तेलीबांधा के ऑन द रॉक्स बार में चाकूबाजी, स्टेशन रोड में 500 के नोट में ड्रग चाटती लड़की के वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुए लेकिन सरकार सोई रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नशे के बढ़ते कारोबार के कारण ही प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। लूटमार, हत्या, चोरी, डकैती और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पिछले दो सालों में कई गुना बढ़ा है, जिसका असल कारण नशाखोरी ही है। गुजरात का मुद्रा पोर्ट दुनिया भर में अवैध ड्रग्स के कारोबार का मुख्य केंद्र बना हुआ है।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

चार हजार से अधिक घरों में लगे सोलर पैनल

रायपुर। स्वच्छ ऊर्जा को जनआंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देश पर गुक्वार को जिलेभर में एक ही दिन में 100 से अधिक प्रधानमंत्री सूर्य घर सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आयोजित इन सभाओं के माध्यम से नागरिकों को सोलर रूफटॉप प्रणाली, सरकारी सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया और बिजली बिल में होने वाली बचत की विस्तृत जानकारी दी गई। जिले में अब तक 4 हजार से अधिक हितग्राहियों के घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इससे न केवल उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर कई परिवार आर्थिक लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। सभाओं में विद्युत विभाग, विभिन्न बैंकों और अधिकृत वेंडर्स के प्रतिनिधियों ने योजना की पात्रता, ऑनलाइन आवेदन, सब्सिडी, ऋण सुविधा तथा तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। अधिक से अधिक पात्र परिवारों से योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया गया।जिला प्रशासन का मानना है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केवल बिजली बिल कम करने की पहल नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान है।

एक दिन में 5 हजार से अधिक किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन

रायपुर। खेती-किसानी को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में राजनांदगांव जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत एक ही दिन में 5 हजार से अधिक किसानों का फार्मर लैंड आईडी (एग्रीस्टेक) पंजीयन एवं सत्यापन कराया गया। अभियान का उद्देश्य किसानों के भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन कर आगामी धान खरीदी, डिजिटल गिरदावरी और विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराना है। अभियान के दौरान कृषि, राजस्व और पंचायत विभाग ने समन्वित रूप से कार्य किया। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, ग्राम सचिव तथा अन्य मैदानी अमले ने किसानों से संपर्क कर उन्हें निकटतम सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र और चौंस सेंटर तक पहुंचाया। सेवा सहकारी समितियों में विशेष रूप से ऑपरेटर भी तैनात किए गए। कृषि विभाग के अनुसार जिन किसानों की फार्मर लैंड आईडी में सभी खसरे या भूमि का पूरा रकबा दर्ज नहीं है, जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि यदि उनकी फार्मर लैंड आईडी में किसी भी खसरे या भूमि के रकबे की प्रविष्टि छूट गई हो, तो वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र अथवा चौंस सेंटर पहुंचकर समय रहते सत्यापन एवं आवश्यक सुधार अवश्य करा लें।

निश्चय कार्यक्रम से आत्मनिर्भर बन रही महिला बंदी

रायपुर। केंद्रीय जेल रायपुर में महिला बंदियों के सर्वांगीण सुधार और समाज की मुख्यधारा में उनके सम्मानजनक पुनर्वास के लिए एक अनूठी पहल की शुरूआत की गई है। जेल प्रशासन द्वारा संचालित निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे जेल के भीतर ही उनके रोजगार की राह आसान हुई है। केन्द्रीय जेल रायपुर में विभिन्न अपराधों के तहत बंद 60 महिला बंदियों को बेसिक ऑफ पिकल (अचार) एवं मसाला निर्माण के व्यावसायिक उत्पादन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिला बंदियों को स्वयं की व्यावसायिक इकाई स्थापित करने के योग्य बनाना है।प्रशिक्षण के दौरान इन बंदियों को खाद्य उत्पादों के निर्माण और उनकी उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता, पैकेजिंग एवं सुरक्षित भंडारण से संबंधित व्यावहारिक जानकारीयां दी गई। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिला बंदियों ने जेल के महिला प्रकोष्ठ में ही नियमित रूप से अचार का निर्माण शुरू कर दिया है। महिला बंदियों द्वारा जेल के भीतर पूरी स्वच्छता के साथ आम, नींबू, गाजर और लहसुन जैसी विभिन्न वैरायटियों के स्वादिष्ट और हाइजीनिक अचार तैयार किए जा रहे हैं। इन गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की बिक्री के लिए व्यवस्था की गई है।

महाराष्ट्र मंडल का शपथ ग्रहण समारोह 26 को

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल की नई कार्यकारिणी (2026-28) का शपथ ग्रहण समारोह रविवार, 26 जुलाई को आयोजित किया गया है। समारोह में अध्यक्ष अजय मधुकर काले और उनके नेतृत्व में 14 सदस्यीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण होगा। पहले ही सभी कार्यकारिणी सदस्यों को उनके प्रकल्प सहित अन्य कार्यभार सौंपे जा चुके हैं। सचिव चेतन गोविंद दंडवते ने बताया कि संत ज्ञानेश्वर सभागृह में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 17 समिति और 17 महिला केंद्रों के पदाधिकारी भी समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। पहली बार महाराष्ट्र मंडल में शिवाजी महाराज कार्यक्रम आयोजन समिति गठित की गई है। इस समिति के समन्वयक अभिषेक विद्याधर बक्षी के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी भी शपथ लेंगे। इनके अलावा भी कुछ समितियों को नई जिम्मेदारियों व कार्यक्रमों के साथ गढ़ा गया है, तो कुछ समितियों को दो नए भागों में बांटकर नई जिम्मेदारियां व कार्यक्रम भी सौंपे गए हैं। इन तमाम समितियों के पदाधिकारी भी इस समारोह में शपथ लेंगे।

सिविल लाइंस सिंधी पंचायत ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय



रायपुर। पूज्य सिविल लाइंस सिंधी पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत के संरक्षक, पार्षद एवं एमआईसी सदस्य अमर गिदवानी का पुष्पगुच्छ एवं शाल-श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया तथा उनके जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर शुभकामनाएं दी गईं। बैठक में समाजहित एवं जनसेवा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पंचायत द्वारा समाज के मेधावी एवं प्रतिभावान बच्चों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद मजदूरों, सब्जी विक्रेताओं, ठेला एवं गुमटी संचालकों को निःशुल्क छतरियों का वितरण किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के तहत ग्राम गोदवारा, अमलेश्वर एवं भाटा में सुरक्षित स्थानों का चयन कर वृक्षरोपण किया जाएगा तथा पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी पंचायत द्वारा निभाई जाएगी।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026

वैज्ञानिक सोच और नवाचार से सतत विकास का संकल्प

रायपुर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सीकोस्ट) द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित 32वाँ राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 के अंतर्गत जिला समन्वयकों एवं रिसोर्स शिक्षकों के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को रीजनल साइंस सेंटर, रायपुर में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेशभर के शिक्षकों एवं जिला समन्वयकों को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की नई थीम, परियोजना निर्माण प्रक्रिया, वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति तथा मूल्यांकन प्रणाली से अवगत कराना था, ताकि अधिकाधिक विद्यार्थी स्थानीय समस्याओं पर आधारित वैज्ञानिक



परियोजनाएं तैयार कर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। कार्यशाला का आयोजन प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री सोनमणी बोरा तथा महानिदेशक, छत्तीसगढ़ विज्ञान आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। ब्लॉक, एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं रीजनल साइंस सेंटर श्री प्रशांत कविश्वर के मार्गदर्शन में किया गया।

विद्यार्थियों को विज्ञान एवं अनुसंधान से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस देश का एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जो 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं अनुसंधान से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए स्थानीय समस्याओं की पहचान करते हैं, आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण करते हैं तथा नवाचार के साथ आम, नींबू, गाजर और लहसुन जैसी विभिन्न वैरायटियों के स्वादिष्ट और हाइजीनिक अचार तैयार किए जा रहे हैं। इन गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की बिक्री के लिए व्यवस्था की गई है।

विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान क्षमता और नवाचार आधारित सोच विकसित करना इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिक ई एवं राज्य समन्वयक डॉ. जे. के. राय, वैज्ञानिक डॉ. डॉ. ए. के. पाठक, वैज्ञानिक डॉ. डॉ. अमित दुबे, राज्य अकादमिक समन्वयक प्रो. (डॉ.) केशव कांत साहू तथा वनस्पति विज्ञान के वरिष्ठ शिक्षाविद डॉ. वी. के. कानुनगो कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी वकाओं ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 की थीम साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी की प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान क्षमता और नवाचार आधारित सोच विकसित करना है।

दण्डवत् प्रणाम रैली निकालते विधानसभा घेराव के लिए निकले, धरना स्थल के गेट पर पुलिस ने रोका

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे डीएड अभ्यर्थियों का धरना गुस्वार को 206वें दिन भी जारी रहा। न्याय की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने नया रायपुर स्थित धरना स्थल से दण्डवत् प्रणाम रैली निकालते हुए विधानसभा घेराव के लिए कूच किया। हालांकि विधानसभा की ओर बढ़ रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने धरना स्थल के मुख्य गेट पर ही रोक दिया।आंदोलनकारी डीएड अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि



न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सरकार और प्रशासन 2,300 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह केवल अभ्यर्थियों के अधिकारों का ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका के आदेशों की भी अवहेलना है। अभ्यर्थियों ने कहा कि भारत के संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, लेकिन 206 दिनों से लगातार चल रहे उनके अनशन के बावजूद सरकार

की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार संघर्षरत अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रशासनिक तंत्र अब संविधान और अदालत के आदेशों से भी ऊपर हो गया है? डीएड अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने और न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 2,300 रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग दोहराई। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।